जुलाई-अगस्त-सितम्बर-2025, वर्ष 34, अंक 7, 8, 9

उत्तर प्रदेश संदेश

सबको शिक्षा
बेहतर शिक्षा

ऑपरेशन कायाकल्प
(97% विद्यालयों का 19 मानकों पर संतृप्तीकरण)

- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
- बालक, बालिका एवं दिव्यांग बच्चों के लिए पृथक स्वच्छ शौचालय/मूत्रालय
- मल्टीपल हैंड वॉशिंग
- कक्षा-कक्षों में टाइलीकरण
- आधुनिक श्याम पट
- स्वच्छ रसोई घर
- भवन की समुचित रंगाई-पुताई
- रैंप एवं रेलिंग की व्यवस्था
- विद्युत संयोजन वायरिंग एवं उपकरण
- सबमर्सिबल एवं वॉटर सप्लाई
- स्वच्छता एवं साफ-सफाई
- किताबों के साथ पुस्तकालय
- फर्नीचर की उपलब्धता
- स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं

प्रोजेक्ट अलंकार
(2,295 विद्यालयों में 27 मापदंडों की मैपिंग)

शैक्षणिक

- कक्षा कक्ष
- प्रयोगशाला
- पुस्तकालय
- कंप्यूटर लैब
- वाई-फाई
- स्मार्ट क्लास
- फर्नीचर

सह शैक्षणिक

- खेल का मैदान
- ओपन जिम
- बहुउद्देशीय हॉल
- आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष
- व्यावसायिक शिक्षा कक्ष
- बैंड तथा साउंड सिस्टम

मूलभूत अवस्थापना

- प्रधानाचार्य कक्ष
- स्टाफ कक्ष
- पेयजल
- बालक शौचालय
- बालिका शौचालय
- चहारदीवारी
- कार्यालय कक्ष

अन्य अवस्थापना

- बिजली व्यवस्था
- बायोमेट्रिक मशीन
- सी.सी.टी.वी. कैमरा
- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
- सोलर पैनल स्थापना
- अग्निशमन यंत्र
- साइकिल स्टैंड

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

काम दमदार
डबल इंजन सरकार

जुलाई, अगस्त, सितम्बर-2025, (संयुक्तांक) वर्ष 34, अंक 7, 8, 9

उत्तर प्रदेश
संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
विशाल सिंह
सूचना निदेशक

सम्पादकीय परामर्श :
अरविन्द कुमार मिश्र
अपर निदेशक, सूचना

चन्द्र विजय वर्मा
सहायक निदेशक/संपादक

अजय कुमार द्विवेदी
सहयुक्त संपादक

दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक, सूचना

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 9919874392, 7705800978

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित

भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

- जनांदोलन बन चुका है डिजिटल इंडिया — 3
  -प्रधानमंत्री
- योगी सरकार में नौकरियों की बहार — 6
  -रश्मि श्रीवास्तव
- पौधरोपण के नए इतिहास ने बदल दी यूपी की आबोहवा — 9
  -प्रद्युम्न तिवारी
- आधुनिक भागीरथ बने मुख्यमंत्री योगी — 14
  -जितेन्द्र शुक्ला
- खुशहाल होते अन्नदाता — 18
  -रूद्रेश घिल्डियाल
- प्रगति के निरंतर कीर्तिमान रचता यूपी — 22
  -सियाराम पांडेय 'शांत'
- देश की शान : शुभांशु का सम्मान — 25
  -पायल लक्ष्मी सोनी
- बालवाटिका से निपुण होंगे नौनिहाल — 28
  -डॉ. सुयश मिश्रा
- मुख्यमंत्री सुपोषण योजना : उत्तर प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य — 33
  -डॉ. शिवानी कटारा
- युवा उद्यमी-प्रदेश की पहचान — 37
  -प्रदीप कुमार गुप्ता
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में... — 41
  -सुधा मिश्रा
- रोजगार महाकुम्भ 2025 : युवाओं के सपनों को मिली नई उड़ान — 44
  -अनिल श्रीवास्तव
- उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रतिबद्ध है योगी सरकार — 47
  -डॉ. अजय कुमार मिश्रा
- विकसित भारत की आधारभूमि उत्तर प्रदेश — 51
  -डॉ. दीपक कोहली
- रामायण सर्किट : अयोध्या से जनकपुर धाम की यात्रा होगी आसान — 54
  -यशोदा श्रीवास्तव
- पं. दीनदयाल उपाध्याय — 57
  -डॉ. सौरभ मालवीय
- प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे कल्याण सिंह — 62
  -वीरेन्द्र सिंह लोधी

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं को भी अपने विकास के मॉडल में शामिल किया और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए सूबे में वृहद पौधरोपण अभियान की शुरुआत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 09 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया। 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' थीम के अंतर्गत पौधरोपण महाभियान-2025 में पूरे प्रदेश में शाम छह बजकर छह मिनट तक एक दिन यानि 09 जुलाई, 2025 को 37,21,40,925 पौधरोपण हुए। उल्लेखनीय है कि यह सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य 37 करोड़ से 21,40925 अधिक रहा। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से इस अभियान का श्रीगणेश करने के बाद आजमगढ़ और गोरखपुर में भी पौधरोपण कर सकारात्मक संदेश देने में देर नहीं की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते आठ वर्षों में राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस दौरान 204 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया, जिनमें से 75 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में वनाच्छादन बढ़ा है। सरकार की सोच थी कि किस तरह से हीटवेव को ग्रीनवेव बदला जाये। इसके लिए किए गये प्रयास न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप पौधरोपण महाभियान-2025 ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के तहत पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड 37.21 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। पूरे प्रदेश के सभी मण्डल व जिलों में योगी सरकार के सभी विभागों, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के समन्वय से के पौधरोपण किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पौधरोपण अभियान सिर्फ पौधरोपण करने का ही कार्य नहीं है, बल्कि यह वर्तमान को संजोने और भविष्य को बचाने का अभियान है।

सम्पादक

जनांदोलन बन चुका है डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बीते एक दशक में यह जनांदोलन बन चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का केन्द्र है और भारत को दुनिया का विश्वसनीय नवाचार साझेदार बना रहा है। हम डिजिटल गवर्नेंस से आगे बढ़कर वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं।

दस साल पहले, हमने एक ऐसे क्षेत्र में पूर्ण विश्वास के साथ ऐसी यात्रा शुरू की थी, जहां पहले कोई नहीं गया था। जहां दशकों तक यह संदेह किया गया कि भारतीय तकनीक का उपयोग कर पाएंगे या नहीं, हमने उस सोच को बदला और भारतीयों की तकनीक उपयोग करने की क्षमता पर विश्वास किया। जहां दशकों तक सिर्फ यह सोचा गया कि तकनीक का उपयोग अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करेगा, हमने उस मानसिकता को बदला और तकनीक के माध्यम से उस खाई को खत्म किया।

जब नीयत सही होती है, तो नवाचार वंचितों को सशक्त करता है। जब दृष्टिकोण समावेशी होता है, तो तकनीक हाशिये पर खड़े लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है। यही विश्वास डिजिटल इंडिया की नींव बना– एक ऐसा मिशन, जो सभी के लिए पहुंच को लोकतांत्रिक (आसान) बनाने, समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुआ। वर्ष 2014 में इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, डिजिटल साक्षरता कम थी और सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बेहद सीमित थी। कई लोगों को संदेह था कि भारत जैसा विशाल और विविध देश वास्तव में डिजिटल बन सकता है या नहीं। आज, इस प्रश्न का उत्तर डाटा और डैशबोर्ड में नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन के माध्यम से दिया जा चुका है। शासन से लेकर शिक्षा, लेन–देन व निर्माण तक डिजिटल इंडिया हर जगह है।

वर्ष 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का

11 गुना है, अब दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है। भारत का 5 जी रोलआउट विश्व में सबसे तेज रोलआउट्स में से एक है और मात्र दो वर्षों में 4.81 लाख बेस स्टेशंस स्थापित किए गए हैं। हाई–स्पीड इंटरनेट अब शहरों, केंद्रों से लेकर अग्रिम सैन्य चौकियों जैसे (गलवान, सियाचिन और लद्दाख तक) पहुंच चुका है।

इंडिया स्टैक, (जो हमारा डिजिटल बैकबोन है) ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाया है, जो अब सालाना 100 अरब से अधिक लेन–देन करता है। विश्व में होने वाले कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन में से लगभग आधे भारत में होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे नागरिकों को हस्तांतरित की गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और 3.48 लाख करोड़ रुपये की लीकेज रोकी गई है। स्वामित्व जैसी योजनाओं ने 2.4 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी काड्र्स जारी किए हैं और 6.47 लाख गांवों को मैप किया है, जिससे वर्षों से चली आ रही भूमि संबंधी अनिश्चितता का अंत हुआ है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को सशक्त बना रही है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है, जो विक्रेताओं और खरीदारों के विशाल बाजार से सीधा संपर्क स्थापित कर नए अवसरों की खिड़की खोलता है। गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) आम आदमी को सरकार के सभी विभागों को सामान और सेवाएं बेचने की सुविधा देता है। इससे न केवल आम नागरिक को विशाल बाजार मिलता है, बल्कि सरकार की बचत भी होती है।

कल्पना कीजिए, आप मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आपकी क्रेडिट योग्यता को अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से आंका जाता है। आपको लोन मिलता है, आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। आप जीईएम पर पंजीकृत होते हैं, स्कूलों और अस्पतालों को सप्लाई करते हैं, फिर ओएनडीसी के जरिये इसे और बड़ा बनाते हैं। ओएनडीसी ने हाल ही में 20 करोड़ लेन–देन का आंकड़ा पार किया है–जिसमें पिछले 10 करोड़ सिर्फ छह महीनों में हुए हैं। बनारसी बुनकरों से लेकर नागालैंड के बांस शिल्पियों तक, अब विक्रेता बिना बिचौलियों के पूरे देश में ग्राहक तक पहुंच रहे हैं। जीईएम ने 50 दिनों में एक लाख करोड़ रुपये का जीएमवी पार किया है, जिसमें 22 लाख विक्रेता शामिल हैं। इनमें 1.8 लाख से अधिक महिला संचालित एमएसएमई हैं, जिन्होंने 46,000 करोड़ रुपये की आपूर्ति की है। भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)–जैसे आधार, कोविन, डिजिलॉकर, फास्टैग, पीएम–वानी और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को अब

वैश्विक स्तर पर पढ़ा और अपनाया जा रहा है। कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सक्षम किया, जिससे 220 करोड़, क्यूआर–सत्यापित सर्टिफिकेट जारी हुए। डिजिलॉकर, जिसके 54 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को सुरक्षित और निर्बाध तरीके से होस्ट कर रहा है। भारत ने अपनी जी 20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी और 2.5 करोड़ का सोशल इंपैक्ट फंड लॉन्च किया, जिससे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देश समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम अपना सकें।

भारत अब विश्व के शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है, जिसमें 1.8 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। लेकिन यह सिर्फ स्टार्टअप आंदोलन नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी पुनर्जागरण है। भारत में युवाओं के बीच एआई स्किल्स और एआई टैलेंट के मामले में बड़ी प्रगति हो रही है। 1.2 अरब डॉलर इंडिया एआई मिशन के तहत भारत ने 34,000 जीपीयूज की पहुंच ऐसे मूल्य पर सुनिश्चित की है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है–एक डॉलर से भी कम प्रति जीपीयू ऑवर। इससे भारत न केवल सबसे सस्ता इंटरनेट इकॉनमी, बल्कि सबसे किफायती कंप्यूटिंग हब बन गया है। भारत ने मानवता–पहले एआई की वकालत की है। नई दिल्ली डिक्लरेशन ऑन एआई जिम्मेदारी के साथ नवाचार को बढ़ावा देता है। देश भर में एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं।

इंडिया स्टैक, (जो हमारा डिजिटल बैकबोन है) ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाया है, जो अब सालाना 100 अरब से अधिक लेन–देन करता है। विश्व में होने वाले कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन में से लगभग आधे भारत में होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे नागरिकों को हस्तांतरित की गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और 3.48 लाख करोड़ रुपये की लीकेज रोकी गई है।

अगला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी होगा। हम डिजिटल गवर्नेंस से आगे बढ़कर वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड तक। डिजिटल इंडिया अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, यह जनांदोलन बन चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का केंद्र है और भारत को दुनिया का विश्वसनीय नवाचार साझेदार बना रहा है। सभी इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स से कहना चाहता हूं कि दुनिया अगली डिजिटल क्रांति के लिए भारत की ओर देख रही है। आइए, हम वह बनाएं, जो सशक्त बनाता है। आइए, हम ऐसे हल निकालें, जो वास्तव में मायने रखते हों। आइए, हम उस तकनीक के साथ नेतृत्व करें, जो एकजुट करती है, समावेशी बनाती है और उत्थान करती है। ◆

साभार : अमर उजाला, 2 जुलाई, 2025

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

योगी सरकार में नौकरियों की बहार

आठ साल में दी गईं साढ़े आठ लाख से ज्यादा नौकरियां

—रश्मि श्रीवास्तव

योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के लिए उम्मीद की बड़ी किरण साबित हुई है। योगी सरकार ने बीते 8 वर्षों में मिशन रोजगार के तहत प्रदेश में साढ़े आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इनमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य प्रशासनिक विभागों की भर्तियां शामिल हैं। खास बात यह है कि योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका नतीजा रहा कि बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के लोगों को नौकरी मिली। युवाओं में यह भरोसा पैदा हुआ है कि सरकारी नौकरी योग्यता से मिल सकती है। न तो किसी नेता की सिफारिश की जरूरत है और न ही रिश्वत देने की। एक तरह से कहा जा सकता है कि योगी सरकार में नौकरियों की बहार आ गई और युवाओं को अपने सपने साकार करने का समुचित अवसर प्राप्त हुआ। सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए योगी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भारी कमी आई है। 2016 में जहां बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत थी, वह अब घटकर सिर्फ 3 प्रतिशत रह गई है।

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इस विशाल जनसंख्या वाले राज्य में रोजगार सृजन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। योगी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में सत्ता में आने के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। योगी सरकार ने न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश और समाज के विभिन्न वर्गों को समावेशी अवसर प्रदान करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज सामने है।

हाल ही में योगी सरकार ने मिशन रोजगार के तहत 60,244 आरक्षी पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया

है। प्रदेश को अपराधमुक्त बनाने व कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने विगत 8 वर्षों में 2.16 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। पुलिस सुधार में योगी सरकार की अभूतपूर्व पहल ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। जस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी दंगों, अपराध और खराब कानून व्यवस्था के लिए होती थी, वह आज दंगामुक्त और अपराधमुक्त होने में सफल हुआ है। पुलिस के अलावा योगी सरकार ने शिक्षा, राजस्व, आयुष, स्वास्थ्य समेत समस्त सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बड़े पैमाने पर भर्तियां कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

योगी सरकार में हुई भर्तियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी के माध्यम से 95 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2020 से अब तक 35 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। यही नहीं, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए ई–अधियाचन पोर्टल की शुरुआत की गई, जिससे समूह क, ख और ग के पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी आई है। योगी सरकार के इन प्रयासों ने न केवल रोजगार सृजन को गति दी, बल्कि उत्तर प्रदेश को युवा–केंद्रित विकास के पथ पर अग्रसर किया है। मिशन रोजगार के तहत यह उपलब्धि राज्य के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है।

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इस विशाल जनसंख्या वाले राज्य में रोजगार सृजन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। योगी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में सत्ता में आने के बाद से सरकारी नौकरियों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। योगी सरकार ने न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश और समाज के विभिन्न वर्गों को समावेशी अवसर प्रदान करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज सामने है।

इतना ही नहीं, कोविड महामारी के बावजूद भर्ती प्रक्रिया जारी रखी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने 1 अप्रैल, 2017 से 20 मार्च, 2025 तक 48,593 अभ्यर्थियों का चयन किया। सबसे ज्यादा चयन 2019–20 में 13,893 रहा। इसी तरह, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने 46,032 अभ्यर्थियों का चयन किया। इसमें 2022–23 में 11,800 चयन के साथ सर्वाधिक भर्तियां की गईं। यह प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के बढ़ते अवसरों का प्रमाण है। प्रदेश सरकार ने चयन प्रक्रिया को और शुचितापूर्ण बनाने के सिए सख्त कदम उठाए हैं। कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण समय में भी योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर रखने और उसके बाद इसमें तेजी लाकर युवाओं के भविष्य को सशक्त करने के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए। 3.75 लाख से अधिक संविदा पर नौकरी दी गई तो निजी क्षेत्र व एमएसएमई के जरिए दो करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इनमें पेपर लीक की रोकथाम जैसे उपाय शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम–2024 लागू किया, जिसके तहत परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के लिए आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों के खिलाफ भी सख्त नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार

में लिप्त किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है। इसका भी सकारात्मक प्रभाव भर्ती प्रक्रियाओं पर नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार ने समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए नई नीति लागू की है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक संविदा पर काम करना होगा। इस दौरान उनका छमाही मूल्यांकन होगा और 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वालों को सेवा से हटाया जा सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की दक्षता में सुधार होगा।

योगी सरकार का जोर समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व देने पर है। पुलिस भर्ती में कम से कम 20 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह कदम महिलाओं को सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 60 प्रतिशत से अधिक नौकरियां ओबीसी और एससी–एसटी वर्गों को दी गई हैं।

योगी सरकार ने अगले दो वर्षों में 2 लाख और सरकारी नौकरियां प्रदान करने की योजना बनाई है, जिसमें एक लाख भर्तियां इस वर्ष और 1 लाख अगले वर्ष की जाएंगी। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव से डेढ़ करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है। सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज–मुक्त ऋण और प्रशिक्षण योजनाएं भी शुरू की हैं। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने नया भर्ती सेवा निगम बनाने की भी तैयारी की है। इससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण पर अंकुश लगेगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 8.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के सभी वर्गों को अवसर प्रदान करना इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। कुल मिलाकर, योगी सरकार का रोजगार सृजन का प्रयास उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। यूपी में भविष्य में और अधिक अवसरों की संभावना दिखाई देती है। ◆

मो. : 8318870229

पौधरोपण के नए इतिहास ने बदल दी यूपी की आबोहवा

—प्रद्युम्न तिवारी

सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सिर्फ एक ही तत्व को कारण माना जा रहा है, वह पेड़ों की बेतहाशा कटान। यह पेड़ ही हैं जो पर्यावरण को बचाये रखने में मदद करते हैं। जाहिर है कि पौधरोपण जीवन देने जैसा है। हमारा लगाया गया हर पेड़ समाज का रक्षक बनेगा। यह कहा जाता है कि वन हमारी धरती के फेफड़े हैं। पेड़ हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अधिक पौधरोपण से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। व्यक्तिगत प्रभावों को रोकने के अलावा पेड़ों की पारिस्थितिक उपस्थिति भी बहुत बड़ी है। वे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनेक लाभों के अलावा कुछ प्रजातियों में तूफान–रोधी गुण भी होते हैं, जो देश के पूर्वी तट पर बेहद मददगार साबित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों को बचाना है।

सिर्फ सड़कें और पुल बनाना ही विकास नहीं है, मानव को बचाना भी विकास की श्रेणी में आता है। इसके पीछे एक तथ्य यह भी है कि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती दर के लिए वनों की कटाई बड़ी समस्या बन गई है। पेड़ तापमान को नियंत्रित करने और मौसम की स्थिति को वर्षा के अनुकूल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हवा से कार्बन डाईऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा वे हमें लकड़ी, भोजन, ईंधन, कागज आदि भी प्रदान करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा पेड़ जानवरों और पक्षियों का भी घर है। यह भी एक तथ्य है कि पेड़ पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी और अन्य प्रदूषकों के स्तर को कम करने में मदद करते हैं और अपनी लकड़ी में कार्बन का भंडारण करते हैं, जिससे सभी को ताजी हवा मिलती है और ग्लोबल वार्मिंग की दर धीमी होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि पेड़ अक्सर धरती की सतह के लिए आधार का काम करते हैं। बरगद जैसे पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं जो मिट्टी को थामे रखती हैं और सतह को स्थिर रखने में मदद करती हैं। इससे भूस्खलन, चट्टान गिरने और हिमस्खलन के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है। बाढ़ के दौरान पेड़ पानी को सोख लेते हैं, जिससे उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ धीमी गति से बढ़ने वाले पेड़ों

में तूफान–रोधी क्षमता होती है और वे इस प्राकृतिक प्रकोप से राहत प्रदान करने में मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन समस्याओं को भी अपने विकास के मॉडल में शामिल किया। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए सूबे में वृहद पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 9 जुलाई 2025 को नया इतिहास रच दिया। 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' थीम के अंतर्गत पौधरोपण महाभियान–2025 में पूरे प्रदेश में शाम छह बजकर छह मिनट तक एक दिन में 37,21,40,925 पौधरोपण हुए। यह सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य 37 करोड़ से 21,40,925 अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से इस अभियान का श्रीगणेश किया। इसके बाद उसी दिन आजमगढ़ और गोरखपुर में भी पौधरोपण कर सकारात्मक संदेश देने में देर नहीं की।

एक तथ्य यह भी है कि दुनिया भर में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर इस अभियान को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान 'एक पेड़ मां के नाम–2.0' के तहत उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर 'पौधरोपण महाभियान–2025' चलाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के रामपुर हलवारा में सरयू नदी के किनारे त्रिवेणी वाटिका में बरगद, नीम और पीपल के पौधे रोपकर इसे भगवान श्रीराम, धरती माता और जन्मदायिनी माता को समर्पित किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ के सठियांव ब्लॉक के केरमा गांव में एक्सप्रेसवे के किनारे हरिशंकरी वाटिका की स्थापना की, फिर गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में चिलुआताल के समीप पौधरोपण किया।

'पौधरोपण महाभियान–2025' के तहत वन, रक्षा, रेलवे एवं सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेस वे, सड़क, नहर, रेल पटरी के किनारे, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक परिसर, चिकित्सा संस्थान, शिक्षण संस्थान, अन्य राजकीय भूमि, कृषकों की निजी भूमि, नागरिकों द्वारा निजी परिसर में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया गया। सबसे अहम बात यह कि अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए वन विभाग की तरफ से एण्ड्रायड आधारित प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रीयल टाइम अपडेट मिला। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि पिछली सरकारों की तरह पौधरोपण अभियान केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित ना रहे, बल्कि इसे लेकर पूरी

पारदर्शिता और पौधों की प्रभावी मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। यही कारण रहा कि इस साल भी पौधों की जियो टैगिंग की मुकम्मल व्यवस्था की गई। वन विभाग ने भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। यही कारण है कि पल–पल की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपडेट होती रही।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते आठ वर्षों में राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस दौरान 204 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया, जिनमें से 75 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 2017 से 23 तक हरित आवरण में 3.38 लाख एकड़ की वृद्धि हुई। 5 लाख एकड़ क्षेत्र में वनाच्छादन बढ़ा है। सरकार की सोच थी कि किस तरह से हीटवेव को ग्रीनवेव में बदला जाये। इसके लिए किए गये प्रयास न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती है। इसके परिणामस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। सीएम योगी का मानना है कि नियोजित और वैज्ञानिक प्रयासों से विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। सूबे में आठ साल पहले शुरू हुए इस अभियान में शुरुआत में केवल पांच करोड़ पौधे उपलब्ध थे, लेकिन वन विभाग, मनरेगा और निजी क्षेत्र के सहयोग से आज 52 करोड़ पौधे तैयार किए गए हैं। एक तथ्य यह भी है कि पौधरोपण अभियान ने न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाया, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। योगी सरकार द्वारा कार्बन फाइनेंसिंग के माध्यम से किसानों को प्रति पेड़ 6 डॉलर पांच साल तक दिए जा रहे हैं। इसके तहत पिछले साल 25 हजार से अधिक किसानों को यह लाभ मिला और इस साल सात कमिश्नरियों के किसानों को 42 लाख रुपये कार्बन क्रेडिट के रूप में प्रदान किए जाने की योजना है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप पौधरोपण महाभियान–2025 ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के तहत पूरे प्रदेश में रिकार्ड 37.21 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। पूरे प्रदेश के सभी मण्डल व जिलों, योगी सरकार के सभी विभागों एवं सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के समन्वय से पौधरोपण किया गया। इस क्रम में वन विभाग के बाद सर्वाधिक 13.12

> **इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप पौधरोपण महाभियान– 2025 ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के तहत पूरे प्रदेश में रिकार्ड 37.21 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया। पूरे प्रदेश के सभी मण्डल व जिलों, योगी सरकार के सभी विभागों एवं सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के समन्वय से पौधरोपण किया गया। इस क्रम में वन विभाग के बाद सर्वाधिक 13.12 करोड़ से अधिक पौधरोपण का लक्ष्य ग्राम्य विकास विभाग ने प्राप्त किया।**

करोड़ से अधिक पौधरोपण का लक्ष्य ग्राम्य विकास विभाग ने प्राप्त किया। वहीं पौधरोपण महाभियान– 2025 के तहत सोनभद्र जिले ने सबसे ज्यादा 1.58 करोड़ पौधरोपण के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो झांसी, लखीमपुर खीरी और जालौन क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर रहे। सबसे ज्यादा शीशम और सागौन के इमारती पेड़ों की 4–4 करोड़ से अधिक पौध लगाई गई। जबकि फलदार पेड़ों में सबसे ज्यादा जामुन के पौधों का रोपण किया गया। पौधरोपण महा अभियान– 2025 सीएम योगी के विजन के मुताबिक ग्रीन यूपी के सपने को साकार कर रहा है।

इस महाभियान में सबसे ज्यादा 1,58,88,285 पौध रोपण कर सोनभद्र जिले ने प्रदेश के सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया। इस क्रम ने 99,51,686 पौध रोपण के साथ झांसी दूसरे और 96,75,100 पौधरोपण के साथ लखीमपुर खीरी तीसरे स्थान पर रहा। जबकि 95,66,224 पौध रोपण के साथ जालौन चौथे और मीरजापुर पांचवें स्थान पर रहा। वहीं पौध रोपण महाभियान–2025 के तहत एक ओर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 14,05,87,234 पौध रोपण किया। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के बाद ग्राम्य विकास विभाग सबसे अधिक 13,12,99,341 पौधरोपण कर अन्य सभी विभागों की तुलना में आगे रहा। ग्राम्य विकास विभाग का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसी क्रम में कृषि विभाग लगभग 4,15,10,285 तथा उद्यान विभाग ने 1,55,60,100 पौधरोपण के साथ क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया। प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने 1,16,21,635 पौध रोपण कर पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं, पौधरोपण महाभियान में सर्वाधिक शीशम के पौधे लगाए गए। शीशम के 4,45,48,989 पौधे लगाए गये, जबकि 4,32,57,354 पौधरोपण के साथ सागौन दूसरे स्थान पर रहा। पौधरोपण में तीसरे स्थान पर रहे जामुन के 1,84,50,924 पौधे लगाये गये। अर्जुन 1,61,82,985 और अमरूद 1,53,33,140 पौधों के रोपण के साथ चौथे और पांचवे स्थान पर रहे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पौधरोपण अभियान सिर्फ पौधरोपण करने का ही कार्य नहीं है, बल्कि यह वर्तमान को संजोने और भविष्य को बचाने का अभियान है। अपनी इस बात को विस्तार देते हुए उन्होंने साफ कहा था कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के भीषण संकट से जूझ रही है। इसके कारण अनेक चुनौतियां सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अमेरिका के टेक्सास में हाल ही में हुई एक घटना का भी उल्लेख किया, जहां अचानक आई बाढ़ में सैकड़ों बच्चे लापता हो गए। आज के दौर में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आकाशीय बिजली और गर्मी की समस्या चरम पर है। इस मौसम में कभी मूसलाधार बारिश हुआ करती थी आज भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम चक्र के इस बदलाव का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। यह सब मानव के अनियोजित कार्य से हो रहा है। इस अनियोजित कार्य की कीमत विश्व मानवता भुगत रही है।

इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ही नहीं, वरन देश में वनाच्छादन बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया गया। इसी का परिणाम है कि 2017 के बाद प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में पौधरोपण किया जा चुका है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से शुरू किया गया पौधरोपण महाभियान अन्नदाता किसानों के आय में वृद्धि करने का भी सशक्त माध्यम बन गया है। इसके लिए उन्होंने कार्बन क्रेडिट योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत किसानों द्वारा पौधा लगाकर किए गए देखभाल के आधार पर 5 वर्ष बाद सर्वे होता है। पेड़ की प्रगति देखकर प्रति कार्बन क्रेडिट 6 डॉलर का भुगतान अन्नदाता किसानों को किया जाता है। उन्होंने बताया कि कार्बन क्रेडिट के लिए 25 हजार किसानों को 32 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस बार 42 लाख रुपये की राशि वितरित की जा रही है।

स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश हीट वेव से ग्रीन वेव की ओर तेजी से अग्रसर है। वन विभाग की ओर से जारी किए गए वर्ष 2021–22 से लेकर 2024–25 तक रोपित किये गये पौधों की जीवितता लगभग 86.67 प्रतिशत दर्ज हैं। साथ ही इस अभियान के चलते प्रदेश में हरित आवरण और फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक में भी राष्ट्रीय औसत से तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप पौध रोपण का लक्ष्य केवल रिकार्ड संख्या में पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी पर्याप्त देखभाल और सुरक्षा कर पर्यावरण संतुलन की दिशा में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना है। इसी क्रम में वन विभाग ने पौधरोपण की जीवितता सुनिश्चित करने के लिए विशेष मॉनिटरिंग और मूल्यांकन व्यवस्था की है। वन विभाग की अनुश्रवण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021–22 में पौधों की जीवितता 76.87 प्रतिशत, 2022–23 में 83.73 प्रतिशत, 2023–24 में 90.04 प्रतिशत और 2024–25 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार 96.06 प्रतिशत दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2020–21 से 2024–25 के काल में प्रदेश में लगाये गये पौधों में से लगभग 86.67 प्रतिशत से अधिक पौधे जीवित हैं। जो प्रदेश में ग्रीन कवर एरिया और पर्यावरण संतुलन बढ़ाने में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं। पौधरोपण के विशेष अभियान के तहत वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में हरित आवरण में लगभग 5 लाख एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान प्रदेश में वन और वृक्ष आवरण 9.18 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 10 प्रतिशत हो गया है। जिसके तहत प्रदेश में वृक्षावरण में वर्ष 2017 से 2021 के बीच लगभग 2 लाख और 2021 से 2023 के बीच 1.38 लाख एकड़ की वृद्धि हुई थी। जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 5 लाख एकड़ हो चुकी है, इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश हरित आवरण वृद्धि में वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक यूपी के वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षावरण में 3.72 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत 3.41 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक में 2.46 फीसदी की वृद्धि हुई, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.13 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है। जिस आधार पर लगभग 72 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड यानि CO_2 के अवशोषण का अनुमान है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। ◆

मो. : 9935097419, 6388632034

आधुनिक भागीरथ बने मुख्यमंत्री योगी

–जितेन्द्र शुक्ला

यूं तो देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने का सपना आजादी के तुरंत बाद देखा गया था, लेकिन इस पर पहली बार गंभीरता से विचार अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्वकाल में किया गया। जैसा कि हर किसी नई या बड़ी बात के साथ होता है, समाज के अनेक हिस्सों से इसका विरोध भी हुआ। खासकर पर्यावरणवादी कार्यकर्ता नदियों के कुदरती बहाव में किसी तरह के कृत्रिम हस्तक्षेप के विरोधी हैं। विवाद होने पर मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। जिसे न्यायालय ने भी हरी झंडी दे दी। दरअसल, नदियों को जोड़ने के पीछे मकसद देश की जल समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना है। इससे अत्यधिक जल वाली नदियों को उन नदियों से जोड़ा जाना है, जिनमें पानी इतना कम रहता है कि वे अपने क्षेत्र की आवश्यकता पूरी नहीं कर पातीं। बहुत–सी नदियों का पानी बिना उपयोग हुए बहकर समुद्र में चला जाता है या बरसात में उनका पानी बाढ़ के रूप में आबादी के एक बड़े हिस्से पर कहर ढाता है। सोच यह है कि इस पानी से उन इलाकों की जरूरत पूरी की जाए, जहां पानी का अभाव है। इस तरह दोनों क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा।

कमोबेश, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विलुप्त हो रहीं नदियों के पुनरोद्धार, पुराने स्वरूप और अस्तित्व में लाने का बीड़ा उठा रखा है। प्रदेश की 75 छोटी और सहायक नदियों को योगी सरकार नया जीवन दे रही है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों का पालन करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए प्रमुख तकनीकी संस्थानों और 10 अहम विभागों की सहभागिता से समन्वित रणनीति बनाई गई है। नदी पुनर्जीवन कार्य को प्रभावी और सतत बनाने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। साथ ही, जिलों की छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए आईआईटी संस्थानों से तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। योगी सरकार प्रदेश की नदियों के पुनरुद्धार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रही है। इस कार्य में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीबीएयू लखनऊ और आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थान तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये संस्थान हर नदी की भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उपयुक्त पुनर्जीवन योजना बना रहे हैं।

योगी सरकार द्वारा नदियों के कायाकल्प का कार्य वर्ष 2018 से ही मनरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया

था। अब इस कार्य को और अधिक संगठित, तकनीकी और व्यापक स्वरूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत जलधाराओं की सफाई, चैनलिंग, वर्षा जल संचयन और पौधरोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। योगी सरकार द्वारा तैयार किए गए मास्टरप्लान के अनुसार, नदी पुनर्जीवन अभियान को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए 10 विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इनमें सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पंचायती राज, वन–बागवानी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश राज्य जल संसाधन एजेंसी, ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं। इन विभागों के समन्वय से प्रत्येक जिले में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रक्रिया के अंतर्गत, हर मंडल में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त कर रहे हैं। यह समिति पुनरुद्धार की योजनाओं का नियमित परीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य यह है कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त हो। योगी सरकार ने जल संरक्षण और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए जिला गंगा समितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की गई है। ये समितियां स्थानीय स्तर पर नदी तंत्र की निगरानी और जन सहभागिता को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करती हैं कि नदी का पुनर्जीवन सतत और समावेशी प्रक्रिया बन सके।

योगी सरकार द्वारा तैयार किए गए मास्टरप्लान के अनुसार, नदी पुनर्जीवन अभियान को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए 10 विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की है। इनमें सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, पंचायती राज, वन, बागवानी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश राज्य जल संसाधन एजेंसी, ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं। इन विभागों के समन्वय से प्रत्येक जिले में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

इतना ही नहीं, सरकार ने नदियों के पुनरुद्धार के लिए समन्वित रणनीति बनायी है। इसके तहत प्रदेश की हर नदी को उसके स्रोत से लेकर अंतिम संगम बिंदु तक चिह्नित किया जाएगा और संबंधित सभी जनपदों में संयुक्त कार्ययोजना बनाकर जरूरी कदम उठाये जायेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ नदी को फिर से प्रवाहित करना नहीं, बल्कि जल गुणवत्ता, जल उपलब्धता और जैव विविधता को टिकाऊ तरीके से संरक्षित करना भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। निर्देशों के तहत नदियों की जलधारा को सुगम बनाने के लिए डिसिल्टेशन (गाद निकासी), चैनलाइजेशन, कोर्स करेक्शन जैसे तकनीकी उपाय किए जाएंगे। साथ ही अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र विकसित कर वहां सघन पौधरोपण कराना भी अनिवार्य होगा।

साफ है कि योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश की नदियों को "जीवित धरोहर" के रूप में संरक्षित करने की दिशा में, नए युग की शुरुआत है। यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। नदियों के पुनरुद्धार की संयुक्त रणनीति बनाने के लिए बहुत विचार विमर्श हुआ। इसके तहत यह कहा गया कि कोई नदी किसी जनपद से निकलकर अपने संगम क्षेत्र तक जितने भी जनपदों से होकर निकलेगी उन सभी पर नदी पुनरुद्धार का दायित्व होगा। हर जिले को अपने हिस्से में आने वाले नदी के क्षेत्र की सफाई, जलधारा पुर्नस्थापना और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कार्ययोजना तैयार करनी होगी। उसके पुनरुद्धार में संबंधित जिलों को मिलकर संरक्षणात्मक कार्य, जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार, कैचमेंट क्षेत्र में चेक डैम और वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट बनाना होगा। नदी से जुड़ी तालाब श्रृंखलाएं भी चिह्नित कर संरक्षित की जाएंगी।

निर्देशों के क्रम में संबंधित जिलों की प्रशासनिक इकाइयों द्वारा संयुक्त कार्ययोजना बनाई जाएगी। गाद निकालने (डिसिल्टेशन) और नदी की दिशा सुधारने (कोर्स करेक्शन) के लिए उच्च तकनीकी हस्तक्षेप होगा। नदी किनारों पर सघन पौधरोपण और कैचमेंट क्षेत्र में भूमि जल

संरक्षण की योजनाएं लागू होंगी। चेक डैम, रिचार्ज पिट्स और जल संग्रहण ढांचे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही तालाबों और पारंपरिक जलस्रोतों का संरक्षण एवं किनारों पर पौधरोपण अनिवार्य होगा। यह नीति न केवल जल जीवन मिशन और नमामि गंगे जैसे अभियानों को मजबूती देगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। नदियों में सालभर जल प्रवाह बना रहेगा, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय संतुलन कायम होगा।

यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भागीरथ प्रयास ही है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 100 से अधिक छोटी और विलुप्त हो चुकी नदियां फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी हैं। इसी क्रम में सूबे के श्रावस्ती में बूढ़ी राप्ती नदी के पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि आसपास के किसानों को भी राहत मिलेगी। बूढ़ी राप्ती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकी से नदी के संरेखण का चिन्हांकन किया गया और अब इस पर काम शुरू हो चुका है। बूढ़ी राप्ती नदी के पुनरोद्धार का कार्य जनसहयोग और मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बरसात के बाद नदी की सफाई और प्रवाह को पुनः ठीक करने का कार्य वृहद स्तर पर किया जाएगा, ताकि नदी अगले वर्ष अपने स्वाभाविक रूप में लौट सके। बूढ़ी राप्ती नदी की कुल लंबाई 67.03 किमी है, और इसका कैचमेंट एरिया 18356.64 हेक्टेयर है। नदी का 16.91 किमी हिस्सा अवरोधित है, जबकि शेष 51.12 किमी का हिस्सा स्वाभाविक रूप में मौजूद है। इस पुनरोद्धार कार्य में नदी के प्रवाह क्षेत्र को सुधारने का प्रयास किया जाएगा।

बूढ़ी नदी के पुनर्जीवित होने से आसपास के किसानों को जल आपूर्ति में मदद मिलेगी, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बूढ़ी राप्ती नदी 54 ग्रामों से गुजरती है और अंत में राप्ती नदी में मिल जाती है। सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि नदी के प्रवाह क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। नदी के सफाई कार्य में मिट्टी की मात्रा का आंकलन कर इसे पुनः जीवन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कार्य प्रदेश में जल प्रबंधन के नए मानक स्थापित करने में मदद करेगा और किसान समुदाय को जल आपूर्ति की बेहतर स्थिति प्रदान करेगा। इस पुनरोद्धार कार्य से न केवल पर्यावरणीय संतुलन होगा, बल्कि किसानों को जल आपूर्ति में भी सुधार मिलेगा। नदी के पुनर्जीवित होने से आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए अधिक पानी मिलेगा, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों को सहारा मिलेगा।

वहीं, दूसरी ओर कानपुर नगर की सूख चुकी नून नदी अब दोबारा बहने लगी है। एक समय जो नदी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, नक्शे से गायब, गाद से भरी, अतिक्रमण से दब चुकी थी, वह अब जलधारा बनकर फिर से जीवन देने लगी है। नून नदी का यह पुनर्जागरण न केवल कानपुर नगर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणादायक मॉडल बन चुका है। यह बताता है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति,

प्रशासनिक सक्रियता और जनता की भागीदारी एक साथ आती है, तो मिट चुकी नदियां भी फिर से जीवनदायिनी बन सकती हैं। नून नदी, जो कभी बिल्हौर, शिवराजपुर और चौबेपुर के खेतों को सींचती थी, बच्चों के खेल की साक्षी थी और ग्रामीण संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थी, वह नदी उपेक्षा की शिकार हो चुकी थी। न तो उसमें पानी बचा था, न कोई पहचान। अतिक्रमण और गाद ने धारा को पूरी तरह बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच थी कि प्रदेश की उन नदियों को फिर से जिंदा किया जाए, जो किसी समय समाज और प्रकृति का हिस्सा थीं। नून नदी का चयन इस योजना के आदर्श मॉडल के रूप में हुआ।

48 किमी. लंबी नून नदी का पुराना रास्ता खोजने में राजस्व अभिलेख, ग्रामीणों की यादें, ड्रोन सर्वेक्षण और सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया गया। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि कहां से बहती थी नदी और कैसे गायब हो गई। इसके बाद मनरेगा योजना के तहत सफाई, खुदाई, गाद निकासी और तटबंध निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। इसके तहत करीब 6,000 श्रमिकों ने 58 ग्राम पंचायतों से मिलकर करीब 23 किलोमीटर की खुदाई और सफाई का कार्य किया। मशीनों की जगह श्रमिकों के श्रम का उपयोग किया गया, जिससे न केवल काम की संवेदनशीलता बनी रही, बल्कि रोजगार भी मिला। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 57 लाख रुपए खर्च हुए और 23,000 से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ।

उधर, प्रदेश के जौनपुर जनपद में गोमती नदी की सहायक पीली नदी का जनसहयोग से पुनरोद्धार किया गया। इससे पीली नदी अपने पुराने स्वरूप में दिखने लगी है। वहीं नदियों के किनारे पौधों को रोपा गया है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और किसानों को फायदा मिले। दरअसल, जौनपुर में बहने वाली पीली नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 61.2 किमी है, जिसमें से 43 किमी जौनपुर में प्रवाहित होती है। यह नदी बदलापुर तहसील के देहुणा गांव से निकलकर भलुआ, खनपुर, बहुर, सिरिकना, रामपुर आदि गांव से गुजरती हुई बेलवां गांव के पास गोमती नदी में मिल जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह नदी जौनपुर की सामाजिक स्मृतियों में गहराई से रची बसी है। ◆

खुशहाल होते अन्नदाता

–रूद्रेश घिल्डियाल

कृषि इस देश के जीवन पद्धति और संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे प्रदेश की अधिकांश श्रम शक्ति और आर्थिक नीति कृषि पर ही आधारित है। खाद्यान्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति कृषि से ही होती है। कृषि विकास से ही गांवों की बड़ी जनसंख्या को उनके क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुलभ कराये जा सकते हैं। समृद्ध राष्ट्र के लिए विकसित कृषि तथा सम्पन्न किसान का होना आवश्यक है, इसलिए आज प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए किसानों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित होना लाजिमी है। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई के पूरक के रूप में असहयोग आंदोलन के दिनों में प्रारम्भ होकर आजादी मिलने तक चलता रहा। किसान आंदोलन में जुटे अनेक किसान नेता उत्तर प्रदेश की धड़कन बनकर जिए और सितारों की तरह चमके। इसमें प्रमुख है बाबा रामचन्द्र, मुंशील कालका प्रसाद, केदार नाथ जी, डॉ. जेड.ए. अहमद, स्वामी सहजानन्द, झारखण्डे राय, सरजू पाण्डेय, गेंदा सिंह, बाबा राघव दास और चौधरी चरण सिंह जो आजीवन किसानों के हितों के लिए लड़ते रहे। तीसरी दुनिया के अधिसंख्य देश गांवों के देश हैं, लेकिन इनका सिरमौर भारत है। राष्ट्रीयता एक किन्तु विभिन्न संस्कृतियों व भाषा के इस देश में ग्रामीण व प्राकृतिक सम्पदा की प्रमुखता के साथ विविधता में एकता के प्रदर्शन यहां के गांवों में साफ परिलक्षित होते हैं।

यही कारण है कि जब वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया बने तो प्रदेश के किसानों को लगा कि स्व. चौधरी चरण सिंह के बाद यह दूसरे किसान नेता हैं, जिनके दिल में किसानों के लिए सम्मान और आँखों में प्यार का दरिया लहराता नजर आता है। मुख्यमंत्री के रूप में उनके दुःख व सुख में भागीदार बनकर समस्याओं से रूबरू होकर समाधान करना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने केवल कागज पर आदेश देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं थी बल्कि नई संस्कृति ईजाद करके किसान पंचायत बुलाकर आमने–सामने उनके दुख दर्द को समीप से सुना और वहीं पर उन्हें पूरा करने का दृढ़संकल्प भी दोहराया। साथ ही उन्हें स्पष्ट शब्दों और खुले दिल से पंजाब व हरियाणा के किसानों के समान समृद्ध बनाने का विश्वास भी दिलाया। वर्तमान सरकार के सभी मामलों के निर्णय का आधार ही जब इंसाफ और इंसानियत का है तो प्रदेश के किसानों को इंसाफ दिलाने से भला कौन रोक सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व धरतीपुत्र

चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन पर किसान रैली आयोजित कर उसे प्रत्येक वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर किसानों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया, जिससे किसानों के मन में सरकार के प्रति असीम विश्वास लौटा है, जो प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए रामबाण साबित रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने की नींव हमारे गांव व किसान ही हैं। जिसे वर्तमान मुख्यमंत्री ने बखूबी समझा। जब किसान समृद्ध और खुशहाल होगा, तो देश का कोना–कोना सोना उगलेगा।

मुख्यमंत्री ने जब गांव को मन्दिर और किसान को सबका भगवान माना है तो उसकी पूजा–अर्चना के बिना तो किसी का कल्याण होने से रहा। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार गांव व किसान ही है। वे जब आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ–साथ उद्योग धंधे भी पनपेंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की कोशिश है कि गांवों के उत्पादन के साथ औद्योगिक विकास की नीति को भी जोड़ा जाय ताकि विकास की गति को और तेज किया जा सके।

उन्होंने किसानों को हर प्रकार की सुविधा और सहायता सुलभ कराने के लिए अधिकारियों को कड़े आदेश दिये।

इसमें किसी प्रकार की कोताही पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। यदि किसानों को इंसाफ मिलने में कोई शंका हो तो वह सीधे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने जब गांव को मन्दिर और किसान को सबका भगवान माना है तो उसकी पूजा–अर्चना के बिना तो किसी का कल्याण होने से रहा। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार

गांव व किसान ही है। वे जब आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ–साथ उद्योग धंधे भी पनपेंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की कोशिश है कि गांवों के उत्पादन के साथ औद्योगिक विकास की नीति को भी जोड़ा जाय ताकि विकास की गति को और तेज किया जा सके। क्योंकि प्रदेश में कृषि के साथ–साथ अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं और कई क्षेत्रों में तो विश्व प्रसिद्ध कुटीर और ग्रामीण उद्योग पनपने की सम्भावनाएं अधिक हैं। किसानों को राहत देने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि यदि किसान के पास किसी भी सरकारी संस्था की बकाये की रसीद होगी और उसका भुगतान समय पर नहीं हो पाया है, तो राजस्व वसूली के लिये ऐसे किसानों को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। इसके लिये सरकार शीघ्र ही ऐसी योजना तैयार कर रही है कि भविष्य में किसानों के सामने ऐसी स्थिति नहीं आयेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों में वर्तमान समय के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदर्शन के 'कृषि दर्शन' में अनेक कृषि प्रधान कार्यक्रम रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि 15 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गये हैं ताकि इस कार्ड से बिना किसी लिखा–पढ़ी के किसी भी तरह का कर्ज मिल सके। यही नहीं, सरकार ने एक लाख रुपये तक के फसली कर्ज पर पड़ने वाली स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरह माफ कर दिया है। पहले फसली ऋण पर चार प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ली जाती थी। किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के साथ किसान पंचायत में 12 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और तीन घंटे अधिक विद्युत हर हाल में आपूर्ति करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। धान उपलब्ध कराने तक उसकी खरीदारी के लिए धान खरीद केन्द्रों की स्थापना की गयी है। ताकि किसानों को धान बेचने के लिए इधर–उधर न भटकना पड़े।

ज्ञातव्य है कि सरकार ने लक्ष्य से अधिक धान खरीदकर रख लिया है। कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले टैक्स

को भी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा खेती के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों को पंजीकरण से मुक्त करके किसानों को काफी राहत पहुंचायी गयी है। उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग में आने वाले उर्वरकों में कई तरह की छूट दी है। जैसे फास्फेटिक एवं पोटेशिक पर चार प्रतिशत व्यापार कर समाप्त कर किसानों से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत एन.टी.पी.सी. से उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। किसानों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट पर कृषि विभाग की वेबसाइट शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। गेहूं की खरीद के लिए 6 मंत्रियों की समिति बनाने की घोषणा के साथ ही किसानों की समस्याओं के जल्द निराकरण करने के लिए कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 'कृषक हेल्प लाइन' की व्यवस्था की गयी है।

किसानों को राहत देने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि यदि किसान के पास किसी भी सरकारी संस्था की बकाये की रसीद होगी और उसका भुगतान समय पर नहीं हो पाया है, तो राजस्व वसूली के लिये ऐसे किसानों को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। इसके लिये सरकार शीघ्र ही ऐसी योजना तैयार कर रही है कि भविष्य में किसानों के सामने ऐसी स्थिति नहीं आयेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों में वर्तमान समय के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदर्शन के 'कृषि दर्शन' में अनेक कृषि प्रधान कार्यक्रम रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि 15 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गये हैं ताकि इस कार्ड से बिना किसी लिखा-पढ़ी के किसी भी तरह का कर्ज मिल सके।

इसके अलावा किसानों की मदद के लिए 'किसान बन्धु' का गठन किया गया है। किसानों की और अधिक समृद्धि और खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ ने उद्यमियों को प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए एग्रोटेक 2000 में आमंत्रित किया है। इससे किसान अपने सरप्लस उत्पादन की जगह अन्य किसी आधारित उद्योगों से लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री जब यह कहते हैं कि विकास का रास्ता खेत-खलिहानों और गांव के गलियारों से होकर जाता है तो उनका स्पष्ट मत है कि कृषि उत्तर प्रदेश की काया है। गांव भारतीय अर्थशास्त्र के प्राण हैं और गांव के किसान इस अर्थव्यवस्था के कर्मठ तपस्वी और प्रदेश के विकास की धुरी हैं। ◆

मो. : 9453059581

प्रगति के निरंतर कीर्तिमान रचता यूपी

–सियाराम पांडेय 'शांत'

उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के गठन के दिन से ही उत्तर प्रदेश समग्र विकास की दिशा में सतत सचेष्ट है। राज्य मंत्रिमंडल की जितनी बैठकें योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई हैं,उतनी शायद ही किसी पूर्ववर्ती सरकार में हुई हो। हर सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठकों की अनिवार्यता का तो सवाल ही नहीं उठता। मंत्रिमंडल की हर बैठक में जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर न केवल चर्चा–परिचर्चा हुई है,बल्कि उनके व्यापक क्रियान्वयन की रणनीति भी बनी है। पिछले प्रस्तावों के अमल और उसमें आने वाली परेशानियों पर मंथन भी हुआ है। सरकार विकास योजनाओं को लेकर सिर्फ मंत्रियों तक ही सीमित नहीं है। वह विधायकों,ग्राम प्रधानों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को भी विकास के मोर्चे पर पूरी ऊर्जा के साथ लगाने में पीछे नहीं रही है। जनसंवादों और ग्राम चौपालों के जरिए। सरकार ने विकास के प्रयासों को गति दी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर उभरा है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने विकास की बड़ी छलांग लगाई है। प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यूं तो विकास की दृष्टि से योगी सरकार ने हर दिन का बेहतर इस्तेमाल किया है। बड़े अधिकारियों के गांवों में रात्रि प्रवास और जन चौपालों के आयोजन की व्यवस्था कर रखी है, जिससे आमजन के फीडबैक सरकार को निरंतर मिलते रहें और वह अपनी रीति–नीति में सुधार– परिष्कार कर उसे जन सापेक्ष बना सके। जुलाई 2025 में सरकार ने जन हित में कई बड़े निर्णय लिए। 3 जुलाई को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होने वाले 30 प्रस्तावों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई।

इनमें औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, पूर्व सैनिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार से संबंधित के अहम प्रस्ताव शामिल रहे। इन फैसलों से न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा, वरन युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे।

इन निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय लखनऊ जिले में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए 49.96 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण को स्वीकृति देने का भी था। इस परियोजना पर 4,776 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। सरकार के इस फैसले से

राजधानी लखनऊ के औद्योगिक विकास को तो गति मिलेगी ही,यातायात सुविधाओं में भी इजाफा होगा।

इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर न केवल आपस में जुड़ जाएंगे बल्कि वहां के लोगों को आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। लखनऊ महानगर भी जाम की समस्या से निजात पा सकेगा। कैबिनेट की इसी बैठक में नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड को विकसित करने का भी बड़ा और अहम फैसला किया गया। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 4700 करोड़ रुपए की लागत वाली न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना प्रस्ताव की मंजूरी कमोवेश इसी रूप में देखी –समझी जा सकती है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण के लिए जमीन सरकार पहले ही मुहैया करा चुकी है। सरकार को पता है कि क्षेत्र के विकास और यहां रहने वाले लाखों–करोड़ों लोगों के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की अहमियत क्या है? सरकार नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड का विकास करना चाहती है और यहां उद्योग–धंधों का जाल बिछाना चाहती है। उसकी कोशिश है कि यहां भारी निवेश आए ताकि रोजगार और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस लिहाज से देखा जाए तो यह निर्णय काफी अहम है।

लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र परियोजना को लेकर भी कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग कर इस परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया। इसी के साथ अब इस परियोजना की कमान लखनऊ विकास प्राधिकरण के हाथों में आ गई है। विकथ्य है कि यह परियोजना कभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करती थी। वर्ष 2017 में जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। यही नहीं,सरकार ने इस परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश भी दिए थे, तभी से ये परियोजना अधर में लटकी पड़ी है।

इस परियोजना के तहत एक राज्य–स्तरीय सभागार और एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। यहां एक आधुनिक खेल परिसर और बहुउद्देशीय खेल मैदान भी बनना है। यही नहीं, यहां पर 750 चार–पहिया वाहनों के लिए बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा का भी निर्माण भी होना है। माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस फैसले से अब यह परियोजना जोर पकड़ेगी।

सरकार ने जहां उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है वहीं रोजगार मिशन के तहत अगले 1 साल के अंदर 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर व 1 लाख बेरोजगारों को प्रदेश–देश के अंदर निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जाहिर है,इससे राज्य में रोजगार प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, बड़े निवेशक भी आकृष्ट होंगे। कारखानों में कार्यरत महिला श्रमिकों से संबंधित नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ है, जिससे उन्हें सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्राप्त हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को लेकर सरकार की गंभीरता का भी कंपनियों को सब्सिडी व लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने से प्रकटीकरण हुआ है। सरकार ने जहां उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है वहीं रोजगार मिशन के तहत अगले 1 साल के अंदर 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर व 1 लाख बेरोजगारों को प्रदेश–देश के अंदर निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जाहिर है,इससे राज्य में रोजगार प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, बड़े निवेशक भी आकृष्ट होंगे। कारखानों में कार्यरत महिला श्रमिकों से संबंधित नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ है, जिससे उन्हें सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्राप्त हो सकेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत आने वाले निगमों के लिए 11 प्रकार की वस्तुओं की खरीद अनिवार्य रूप से विभागीय निगमों से करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से पूर्व सैनिकों और होमगार्डों की सेवाएं सीधे लिए जाने की स्वीकृति दी गई है। जेम पोर्टल से इतर यह व्यवस्था पूर्व सैनिकों को सीधे लाभ पहुंचाएगी। अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैंटोनमेंट क्षेत्र में एनएसजी हब सेंटर की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह केंद्र भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करेगा।

वित्त विभाग ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे वित्तीय लेन–देन की प्रक्रिया अधिक दक्ष और पारदर्शी होगी। परिवहन विभाग से संबंधित यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 और 4(9) में संशोधन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके तहत 'वन टाइम टैक्स' की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना है, जिससे राजस्व में वृद्धि संभव हो सके।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। यह तो कैबिनेट की एक बैठक की बानगी भर है। हर सप्ताह मंगलवार को सरकार और उसके मंत्रिमंडल की कोशिश राज्य की जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने की होती है। कौन क्या कहता है,इसकी चिंता किए बगैर सरकार 'हम क्या कर रहे हैं' की रीति–नीति को अमली जामा पहनाने में जुटी है और इसका असर बहुत कुछ दिख भी रहा है। सरकार की कोशिश भौतिक और आर्थिक विकास के साथ नैतिक और सांस्कृतिक विकास की भी है और इस दिशा में उसका प्रयास राज्य के हर आम और खास को दिख भी रहा है। सरकारी योजना हर किसी तक पहुंच रही है, यह अपने आप में सरकार की बड़ी उपलब्धि है। देखा जाए तो जुलाई माह में उत्तर प्रदेश पर विकास की चौतरफा बरसात हुई है। हर क्षेत्र में तरक्की का ग्राफ ऊंचा हुआ है। यह सब सरकार और जनता के समवेत प्रयास से ही मुमकिन हो पा रहा है। विकास का यह पहिया थमे नहीं, इस निमित्त हर क्षण सजग रहने की जरूरत है और यही मौजूदा समय की मांग भी है। ◆

मो. : 7459998968

देश की शान : शुभांशु का सम्मान

—पायल लक्ष्मी सोनी

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने एक्सिओम–4 मिशन–4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा कर इतिहास रचा। 25 अगस्त को वे अपने शहर लखनऊ लौटे। एयरपोर्ट से लेकर शहर की गलियों तक उनका स्वागत देखने लायक था। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके नाम पर नई स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का बड़ा ऐलान भी किया, जिससे प्रदेश के युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने का अवसर मिलेगा।

एयरपोर्ट से सड़कों तक गूंजा स्वागत

25 अगस्त सुबह 8:15 बजे जैसे ही शुभांशु शुक्ला लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, वातावरण 'भारत माता की जय' और 'जय जवान–जय विज्ञान' के नारों से गूंज उठा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलते ही उनका काफिला खुली जीप में सवार होकर शहर की सड़कों से गुजरा। दोनों ओर खड़े लोग तिरंगे लहराते, तालियाँ बजाते और फूल बरसाते दिखाई दिए।

विद्यालयों के छात्र–छात्राओं में भी गजब का उत्साह था। "मैं शुभांशु शुक्ला जैसा बनना चाहता हूँ, ताकि देश को गौरवान्वित कर सकूँ" एक छात्र ने खुशी से कहा। वहीं,

सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (जहाँ से शुक्ला ने शिक्षा पाई थी) ने उनके सम्मान में विशेष परेड और कार्यक्रम आयोजित किया।

ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन

शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुँचने वाले पहले भारतीय बने। 15 जुलाई को संपन्न इस मिशन में उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें इसरो की सक्रिय भूमिका रही। यह अनुभव आने वाले गगनयान मिशन के लिए अमूल्य साबित होगा।

स्कॉलरशिप योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शुक्ला से मुलाकात के दौरान घोषणा की कि प्रदेश सरकार अब "ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्कॉलरशिप योजना" शुरू करेगी। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों को सहायता प्रदान करेगी, जो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं।

सीएम ने कहा, "पहले स्पेस साइंस से जुड़े पाठ्यक्रम बहुत कम सुनाई देते थे, लेकिन आज प्रदेश के कई तकनीकी विश्वविद्यालयों में स्पेस साइंस प्रोग्राम चल रहे हैं। यह स्कॉलरशिप युवाओं को प्रोत्साहित करेगी और भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी।"

सीएम ने कहा, "पहले स्पेस साइंस से जुड़े पाठ्यक्रम बहुत कम सुनाई देते थे, लेकिन आज प्रदेश के कई तकनीकी विश्वविद्यालयों में स्पेस साइंस प्रोग्राम चल रहे हैं। यह स्कॉलरशिप युवाओं को प्रोत्साहित करेगी और भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगी।"

राजनीति से विज्ञान तक, सबका गर्व

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी शुभांशु की उपलब्धियों पर गर्व जताया। इसरो के चेयरमैन वी. नारायणन ने कहा, "2047 तक

विकसित भारत के निर्माण में अंतरिक्ष मिशनों की बड़ी भूमिका होगी। शुभांशु शुक्ला ने इस दिशा में भारत के कदमों को और मजबूत किया है।"

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने स्वागत भाषण में कहा कि "शुभांशु की उड़ान भारत को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।" इस अवसर पर शुक्ला के परिवार को भी सम्मानित किया गया – उनकी मां आशा शुक्ला को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, पिता शंभू दयाल शुक्ला को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने और पत्नी डॉ. कामना शुक्ला को महापौर सुषमा खर्कवाल ने अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने एक्सिओम–4 मिशन–4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा कर इतिहास रचा, सोमवार को अपने शहर लखनऊ लौटे। एयरपोर्ट से लेकर शहर की गलियों तक उनका स्वागत देखने लायक था। और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके नाम पर नई स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का बड़ा ऐलान भी किया, जिससे प्रदेश के युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने का अवसर मिलेगा।

नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

इस समारोह में मंत्री, सांसद, विधायक, वैज्ञानिक, अधिकारी और हजारों विद्यार्थी मौजूद रहे। हर कोई इस बात से गौरवान्वित था कि उत्तर प्रदेश के बेटे ने भारत का नाम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुँचाया।

लखनऊ की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब और सरकार की नई स्कॉलरशिप घोषणा ने यह साबित कर दिया कि शुभांशु शुक्ला केवल अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए "आशा के सितारे" बन चुके हैं। ◆

मो. : 9140385403

बालवाटिका से निपुण होंगे नौनिहाल

–डॉ. सुयश मिश्रा

उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा यात्रा अब नौनिहालों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखने जा रही है। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सशक्त, समकालीन और बच्चों के सर्वांगीण विकास के अनुकूल बनाने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को हर बच्चे तक पहुँचाने और शिक्षा की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय मानकों पर खरा उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत न केवल बालवाटिका/प्री–प्राइमरी जैसी नवीन पहल शुरू की जा रही है, बल्कि विद्यालयों का मर्जर कर शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात में संतुलन लाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव आने वाले वर्षों में बच्चों की बौद्धिक, भावनात्मक सामाजिक क्षमताओं को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगा और उत्तर प्रदेश को देश में शिक्षा सुधार का अग्रणी राज्य बनाएगा।

मजबूत होगी नौनिहालों की नींव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव माना गया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को हर बच्चे तक पहुँचाने का संकल्प लिया है। योजना के तहत वर्ष 2026 तक राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बालवाटिका या यूकेजी की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य नौनिहाल कक्षा 1 में प्रवेश करने से पहले ही संगठित, पोषणयुक्त और खेल–आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे उनका बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास संतुलित तरीके से हो। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 70,494 सरकारी विद्यालयों में पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की सुविधा मिलती है। इन केंद्रों को ईसीसीई के ढांचे में शामिल करते हुए। सरकार विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है।

हाल ही में 8,800 विद्यालयों में ईसीसीई शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, जो 41,127 विद्यालय अभी आंगनबाड़ी केंद्र से वंचित हैं, वहां भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ताकि किसी भी क्षेत्र का बच्चा इस सुविधा से वंचित न रह सके। इसके साथ ही, सरकार का ध्यान केवल शिक्षकों की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। ईसीसीई के तहत विद्यालयों में रंगीन, आकर्षक और बच्चों के अनुकूल कक्षाओं का निर्माण, खेल सामग्री की उपलब्धता, और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स की व्यवस्था भी की

जा रही है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पोषण योजनाओं को भी बालवाटिका से जोड़ा जा रहा है, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य का संतुलित मॉडल तैयार हो सके। सरकार का दावा है कि यह प्रयास न केवल बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मज़बूत करेगा, बल्कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतारते हुए उत्तर प्रदेश को बुनियादी शिक्षा सुधार में आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करेगा। आने वाले समय में यह पहल लाखों नौनिहालों के भविष्य को नई दिशा देगी।

बालवाटिका में क्या मिलेगा?

बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बाल वाटिका के अंतर्गत कई अनिवार्य सुविधाओं को लागू करने की योजना बनाई है, जिनमें प्रशिक्षित, संवेदनशील और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है, जो छोटे बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझते हों। साथ ही, खेल और गतिविधि आधारित शैक्षणिक सामग्री जैसे वंडर बॉक्स, वर्कबुक आदि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बच्चों में रचनात्मकता और सीखने की रुचि बढ़े। कक्षाओं में आयु–उपयुक्त फर्नीचर और सुरक्षित, रंग–बिरंगे वातावरण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे बच्चों को सहज और प्रेरक माहौल मिल सके। शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आउटडोर खेल उपकरण लगाए जाएंगे, जबकि पोषणयुक्त मध्याह्न भोजन और आवश्यक स्टेशनरी बच्चों को नियमित रूप से प्रदान की जाएगी। आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास जैसे संसाधनों से स्कूल लैस होंगे जिससे छात्र–छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसके अलावा, अभिभावकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे बच्चों के समग्र विकास में परिवार और समाज का सहयोग भी जुड़े और शिक्षा एक साझा जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़े।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर और समर्पित प्रयास कर रही है। राज्य के कुल बजट का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। शिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और तकनीकों के अनुरूप विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें। शैक्षिक सत्र 2024–25 में प्रदेश के 48,061 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 'निपुण विद्यालय' के रूप में सफल घोषित हुए हैं।

ईसीसीई में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नेतृत्व

जहां पंजाब और असम जैसे राज्य क्रमशः 13,000 और 25,000 विद्यालयों में ईसीसीई को लागू कर चुके हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इसे 1.11 लाख विद्यालयों में एक साथ लागू करने जा रहा है। यह न केवल बड़ा प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय है, बल्कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में देश का सबसे व्यापक प्रयास भी बन गया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को सुदृढ़ शैक्षिक नींव मिलेगी, स्कूल ड्रॉपआउट की दर घटेगी और छात्रों की प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। यह कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 के भी अनुरूप है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने की संस्तुति करता है।

क्या है स्कूल मर्जर नीति?

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के 50 से कम छात्र संख्या वाले सरकारी और परिषदीय विद्यालयों का मर्जर करने की योजना को गति दी है। इस योजना के तहत राज्यभर में करीब 10,000 विद्यालयों को पेयर किया जा चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र–शिक्षक अनुपात में सुधार, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और गुणवत्ता–युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय नया नहीं हैं। वर्ष 2024 में इसकी चर्चा शुरू हुई थी और अब इसे व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा रहा है। स्कूलों को एक–दूसरे से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर ही मर्ज किया जा रहा है, ताकि छात्रों को विद्यालय आने–जाने में असुविधा न हो। मंत्री ने यह भी साफ किया

मिल सके। वहीं, 50 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति पीटीआर के निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा जर्जर भवन में अध्ययन न करे। इस संबंध में जर्जर विद्यालय भवनों की पहचान और उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। इसके अलावा, लगभग 132 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के सभी विद्यालयों का सेफ्टी ऑडिट भी प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित हो सके। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालय परिसर में स्थित को–लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का अवसंरचनात्मक विकास भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों की सुविधा और सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए बालमैत्रिक फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे नौनिहालों के लिए विद्यालय सुरक्षित, आकर्षक और प्रेरणादायक स्थान बन सके। सरकार ने मर्ज किए गए विद्यालयों में शिक्षक–छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए 20,182 शिक्षकों का समायोजन किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अधिक या कम न हो। मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हों और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। मर्जर का मकसद छंटनी नहीं, बल्कि समायोजन और बेहतर प्रबंधन है।" सरकार के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में 11,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि शिक्षा के 19 विभिन्न पैरामीटरों पर खर्च की गई है। इनमें स्कूल भवन, शौचालय, बिजली, पीने का पानी, स्मार्ट क्लास, टेबल–बेंच, खेल सामग्री,

कि किसी भी विद्यालय को पूर्णतः बंद नहीं किया जा रहा है। जो भवन खाली होंगे, उनमें बाल वाटिका या प्री–प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश इस तरह की नीति अपनाने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले राजस्थान में 20,000 विद्यालयों का मर्जर, मध्य प्रदेश में 36,000 विद्यालय पहले चरण में पेयर, ओडिशा में 1,200 स्कूलों की पेयरिंग जबकि हिमाचल प्रदेश में स्कूल पेयरिंग की प्रक्रिया पहले से चल रही है। इन राज्यों से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश ने इस योजना को लागू किया है और राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बताते हुए छात्रों के भविष्य को संवारने की दिशा में आवश्यक कदम मान रही है।

शिक्षकों को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों का खंडन

विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया कि स्कूलों के मर्जर से शिक्षकों के पद खत्म किए जा रहे हैं। इस पर भी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि न तो कोई शिक्षक निकाला जा रहा है और न ही कोई पद समाप्त किया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों एवं रसोइयों के पदों में किसी प्रकार की कमी या समाप्ति नहीं की जा रही है। पेयरिंग की प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों में भी कम से कम तीन शिक्षक (शिक्षामित्र सहित) की तैनाती सुनिश्चित हो, जिससे प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

डिजिटल रजिस्टर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वर्ष 2017 से पहले परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी, उससे आज की स्थिति की तुलना की जाए तो ठोस बदलाव स्पष्ट दिखता है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 27 लाख से अधिक नए नामांकन कराए गए हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी विद्यालयों के प्रति आम जनमानस का विश्वास बढ़ा है।

मर्जर की प्रक्रिया में लचीलापन

हालांकि मर्जर की प्रक्रिया के तहत विद्यालयों को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि किसी क्षेत्र में भौगोलिक कठिनाइयाँ सामने आती हैं या समुदाय से आपत्ति आती है, तो ऐसे मामलों में "अनपेयरिंग" की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुछ क्षेत्रों में यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है।

पिछले 8 वर्षों में बेसिक शिक्षा में सुधार

पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और आधुनिकता को नए आयाम देना है। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,26,410 नए शिक्षकों की भर्ती कर शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। शिक्षा को वर्तमान सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए बच्चों को शिक्षा और सर्वांगीण विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए अंतर्विभागीय कन्वर्जेंस कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11,500 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर प्रदेश के 96 शतप्रतिशत परिषदीय विद्यालयों को 19 मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं से लैस किया गया। इस पहल को नीति आयोग ने अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। राज्य के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। 4,500 करोड़ की लागत से प्रत्येक जनपद में 2 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 1,500 छात्र–छात्राओं को आधुनिकतम शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रति विद्यालय 30 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे ये संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्री–प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, पीएम श्री योजना के तहत, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 1,722 विद्यालय (1,565 परिषदीय एवं 157 माध्यमिक) चयनित किए गए हैं। इन विद्यालयों को इंटरनेट, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाओं, खेल सामग्री, प्रोजेक्ट–आधारित लर्निंग और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगभग 1,199.97 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिससे लगभग 4 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यालयी शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिभावकों के आधार–सीडेड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1,200 प्रति छात्र प्रतिवर्ष यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते–मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी हेतु

अंतरित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025–26 में अब तक 1,200 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है, और शेष विद्यार्थियों के लिए यह प्रक्रिया जारी है। शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों से सशक्त बनाने के लिए, परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2,61,530 टैबलेट्स वितरित किए गए हैं। साथ ही, 31,600 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं केजीबी विद्यालयों को स्मार्ट क्लास और 14,108 विद्यालयों को आईसीटी लैब की सुविधा प्रदान की गई है। इन प्रयासों से न केवल शिक्षण–प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, बल्कि विद्यार्थियों को डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा भी उपलब्ध हो रही है। विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब से पूरी तरह संतृप्त किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी संसाधनों के माध्यम से बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। राज्य में वर्तमान में कुल 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनका संचालन प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

इन विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 82,629 छात्राओं का नामांकन है, जिन्हें आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और अन्य शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी अनुश्रवण किया जाता है। अवसंरचना विकास के अंतर्गत, विद्यालयवार सुविधाओं का चिन्हांकन कर कमी वाले क्षेत्रों का संतृप्तिकरण किया गया है। सभी 746 विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही, 718 डॉरमेट्री (छात्राओं के आवास हेतु), 514 टॉयलेट ब्लॉक और 574 कंप्यूटर लैब भी तैयार की गई हैं, जिससे छात्राओं के लिए सुरक्षित, आधुनिक और सुलभ शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित हो सके।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर और समर्पित प्रयास कर रही है। राज्य के कुल बजट का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। शिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और तकनीकों के अनुरूप विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें। शैक्षिक सत्र 2024–25 में प्रदेश के 48,061 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 'निपुण विद्यालय' के रूप में सफल घोषित हुए हैं। यह उपलब्धि प्रदेश की बुनियादी शिक्षा में आए सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है। स्वतंत्र संस्था 'असर' की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। ◆

मो. : 8924856004

मुख्यमंत्री सुपोषण योजना : उत्तर प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य

–डॉ. शिवानी कटारा

भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या एक ओर पोषण संबंधी चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर सुधार की अपार संभावनाएँ भी खोलती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5, 2019–21) के अनुसार राज्य में लगभग 39 प्रतिशत बच्चे स्टंटेड, 17 प्रतिशत वेस्टेड और 34 प्रतिशत अंडरवेट पाए गए हैं। आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि हर तीसरा बच्चा अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में कुपोषण का सामना कर रहा है। यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि शिक्षा, कार्यक्षमता और राज्य के आर्थिक भविष्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यही कारण है कि सरकार ने पोषण सुधार को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। मई 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुपोषण योजना इस दिशा में ठोस और दूरगामी पहल है, जिसका लक्ष्य बच्चों को बेहतर पोषण, ऊर्जा अवसर देकर स्वस्थ समाज और सशक्त भविष्य का निर्माण करना है।

योजना का स्वरूप

मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक स्नैक्स (नाश्ता) पैकेट उपलब्ध कराना है। पहले चरण में आठ आकांक्षी जिलों को चुना गया और लगभग 11.13 लाख बच्चों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए ₹254.83 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया और प्रति बच्चे प्रतिदिन ₹44 का पैकेट तय किया गया, जिसमें औसतन 400 कैलोरी और 15–20 ग्राम प्रोटीन शामिल है। इसमें मिलेट और मूंगफली से बने न्यूट्री–बार, फ्लेवर्ड दूध और मौसमी फल जोड़े गए हैं, ताकि बच्चों को संतुलित और आकर्षक भोजन मिल सके।

इस व्यवस्था की नींव दो स्तंभों पर टिकी है–आँगनवाड़ी नेटवर्क और Take-Home Ration (THR) मॉडल। आँगनवाड़ी केंद्र पहले से ही राज्य के हर गाँव और शहरी वार्ड में मौजूद हैं। लाखों बच्चे पंजीकृत हैं।

यही केंद्र अब योजना की रीढ़ बन गए हैं, जहाँ कार्यकर्ता बच्चों की उपस्थिति और स्वास्थ्य आँकड़े दर्ज करने के साथ–साथ पौष्टिक पैकेट वितरित करने का काम भी करती हैं। दूसरी ओर THR मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को भोजन केवल आँगनबाड़ी तक सीमित न रहे, बल्कि वे इसे घर ले जाकर परिवार की देखरेख में भी खा सकें। इस संयोजन से न केवल वितरण सुदृढ़ हुआ बल्कि पोषण की निरंतरता भी बनी रहती है।

क्रियान्वयन की ठोस रणनीति

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने व्यावहारिक और ठोस उपाय किए हैं। जिला स्तर पर विशेष THR यूनिट्स और आपूर्ति–श्रृंखला केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि हर गाँव तक पैकेट समय पर पहुँच सके। यह काम स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। साथ ही पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) जैसी डिजिटल प्रणालियाँ लागू की गई हैं, जिनमें हर बच्चे की उपस्थिति, वजन, ऊँचाई और हीमोग्लोबिन का डेटा ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और अधिकारियों को तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है।

मिलेट से पोषण

सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और स्थानीय उद्योगों को भी भागीदार बनाया है। डेयरी कंपनियों और मिलेट–प्रोसेसिंग इकाइयों के सहयोग से दूध, फल और न्यूट्री–बार की आपूर्ति लगातार बनी रहती है। मिलेट्स–जैसे बाजरा, ज्वार, कोदो, कंगनी और रागी स्वास्थ्य और नीति दोनों के लिए अहम हैं। ये अनाज कम पानी में उग जाते हैं, किसानों के लिए सरल हैं और पोषण से भरपूर हैं, इसलिए इन्हें "Nutri-Ccereals" कहा जाता है। न्यूट्री–बार को मिलेट आधारित बनाने से बच्चों को प्रोटीन और आयरन का समृद्ध स्रोत मिलता है, वहीं स्थानीय किसान भी इन फसलों की खेती से अपनी आय बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिल रहा है। वाराणसी में हुए पायलट ने यह भी दिखाया कि बच्चे मिलेट्स–बार को स्वादिष्ट मानते हैं, जिससे योजना की स्वीकार्यता और प्रभाव दोनों बढ़े हैं।

गुणवत्ता और जागरूकता

हर जिले में गुणवत्ता परीक्षण और रैंडम–सैंपल चेकिंग की व्यवस्था है–THR पैकेज का नमूना FSSAI मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जाँचकर सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों तक पहुँचा हर पैकेट सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हो। इतना ही नहीं, मातृ–समूहों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जहाँ

महिलाओं को विविध आहार, स्वच्छता और दूध–फल के सेवन की अहमियत समझाई जाती है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे केवल पैकेट वितरण तक सीमित न रहें, बल्कि परिवारों को पोषण शिक्षा भी दें, ताकि बदलाव गहरा और टिकाऊ हो सके।

जमीनी अनुभव

चित्रकूट : चुनौतियों के बीच जीवनरेखा

चित्रकूट जैसे जिलों के लिए यह योजना जीवनरेखा है, क्योंकि यहाँ लगभग आधे बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं और गरीबी व भौगोलिक कठिनाइयाँ पोषण तक पहुँच को और मुश्किल बना देती हैं। ऐसे हालात में रोजाना मिलने वाला दूध, फल और न्यूट्री–बार बच्चों को न केवल स्वास्थ्य देता है बल्कि उनके भविष्य को भी सशक्त बनाता है। जिले में 1,088 आँगनबाड़ी केंद्र हैं और इनमें लगभग 37,500 बच्चे पंजीकृत हैं। मानिकपुर ब्लॉक के बरुआ गाँव की आँगनबाड़ी की सुबह इस बदलाव की गवाही देती है। कार्यकर्ता सुनीता देवी जब पौष्टिक पैकेट खोलती हैं तो उसमें एक न्यूट्री–बार, एक छोटा दूध पैक और अमरूद जैसा फल निकलता है। बच्चे उत्सुकता से उसे लेने आते हैं। पहले जहाँ मुश्किल से 15 बच्चे आते थे अब रोज 25 से अधिक उपस्थिति होती है।

गाँव के किसान रामसिंह की बेटी गुड़िया की कहानी आँकड़ों को जीवंत बना देती है। चार साल की गुड़िया का वजन पहले सिर्फ 10.5 किलो था और वह बार–बार बीमार पड़ती थी। लेकिन जब से तीन महीने तक उसे नियमित पौष्टिक पैकेज मिलने लगा, उसका वजन लगभग एक किलो बढ़ गया। अब वह घर पर भी फल और अन्य खाना मांगने लगी है। उसकी माँ गर्व से कहती हैं, "अब वह रोज स्कूल जाती है और खेलने–दौड़ने में भी पहले से अधिक सक्रिय हो गई है।"

मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक स्नैक्स (नाश्ता) पैकेट उपलब्ध कराना है। पहले चरण में आठ आकांक्षी जिलों को चुना गया और लगभग 11.13 लाख बच्चों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए ₹254.83 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया और प्रति बच्चे प्रतिदिन ₹44 का पैकेट तय किया गया, जिसमें औसतन 400 कैलोरी और 15–20 ग्राम प्रोटीन शामिल है। इसमें मिलेट और मूंगफली से बने न्यूट्री–बार, फ्लेवर्ड दूध और मौसमी फल जोड़े गए हैं, ताकि बच्चों को संतुलित और आकर्षक भोजन मिल सके।

वाराणसी : पायलट से व्यापक असर तक

वाराणसी की तस्वीर थोड़ी अलग है, लेकिन उतनी ही प्रेरक भी। यहाँ लगभग 4.08 लाख छोटे बच्चे हैं, जिनमें 37 प्रतिशत स्टंटेड, 21 प्रतिशत वेस्टेड और 39 प्रतिशत अंडरवेट हैं। जिले में 3,914 आँगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 1.09 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। पिंडरा ब्लॉक के रामनगर गाँव की आँगनबाड़ी में रंग–बिरंगे पोस्टर दीवारों पर सजे हैं और बच्चे खुशी से कतार में बैठे हैं। कार्यकर्ता रेखा पांडे बच्चों को न्यूट्री–बार और दूध बाँटती हैं। यह वही जगह है जहाँ 2023 में मिलेट–न्यूट्री–बार का पायलट चला था और बच्चों ने उसे पसंद किया था। अब वही मॉडल मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में अपनाया गया है।

रिक्शा चालक रमेश की बेटी नेहा का अनुभव इसका प्रमाण है। नेहा पहले अक्सर बीमार रहती थी और स्कूल से छुट्टी ले लेती थी। अब पिछले दो महीनों में उसकी तबियत बेहतर हो रही है और उसकी हाजिरी नियमित हो गई है। उसकी माँ कहती हैं, "पहले उसे खाना खिलाना मुश्किल होता था। अब वह खुद पैकेट का इंतजार करती है और घर का भी खाना अच्छे से खाती है।"

दोनों जिलों की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि आँकड़े और कहानियाँ जब एक साथ चलते हैं तो बदलाव की तस्वीर और साफ हो जाती है।

सरकार के ठोस कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना की सफलता को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर, उसे जमीनी हकीकत बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स, निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और डेटा–आधारित कार्रवाई पर आधारित ठोस ढांचा तैयार किया है। सरकार द्वारा उठाए गए डेटा–प्रमाणित ठोस कदम इसका प्रमाण हैं।

5. हाल ही में "Addressing Maternal Anaemia in Uttar Pradesh" नामक हैंडबुक जारी की गई है, जो स्वास्थ्य कर्मियों को मातृ एनीमिया रोकने के व्यावहारिक उपाय देती है। NFHS–5 के अनुसार गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर 51 प्रतिशत से घटकर 45.9 प्रतिशत और गंभीर एनीमिया 2.1 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत पर आ गई है। माताओं के स्वास्थ्य पर यह ध्यान सीधे पोषण अभियान और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से जुड़ता है, क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ और पोषित बच्चे की आधारशिला है।

1. अप्रैल 2025 तक राज्य में कुल 204 THR यूनिट्स काम कर रही थीं जो 43 जिलों में 288 पोषण प्रोजेक्ट्स का संचालन कर रही थीं। सरकार ने ₹273.5 करोड़ की आर्थिक व्यवस्था करते हुए 2026–27 तक 347 अतिरिक्त THR यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक पौष्टिक आहार का नियमित प्रवाह सुनिश्चित हो।

2. इसी क्रम में सरकार ने Sambhav Abhiyan 5.0 शुरू किया है, जिसे "Six Months, Seven Times" रणनीति के साथ लागू किया गया है। इसके तहत शिशुओं को जन्म के पहले छह महीनों में सात बार पोषण जांच और स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं। यह पहल पोषण अभियान का हिस्सा है। यह मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को पूरक बनाती है।

3. Poshan Tracker ऐप और पोर्टल से राज्य में हर आँगनवाड़ी केंद्र और पंजीकृत बच्चों का डेटा–उपस्थिति, वजन, ऊँचाई, हीमोग्लोबिन–ऑनलाइन दर्ज होता है।

4. ICDS के 75 जिलों में 897 परियोजनाएँ संचालित हैं, जिनसे 1.82 करोड़ बच्चों, 13.5 लाख गर्भवती महिलाओं और 10.7 लाख स्तनपान कराने वाली माताओं तक पोषण व स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच रही हैं। इनमें से 1.33 लाख गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को विशेष चिकित्सा और आहार दिया गया है। यही व्यापक ढाँचा पोषण अभियान का आधार है, जिस पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना टिककर बच्चों को रोजाना पौष्टिक स्नैक उपलब्ध कराती है।

निष्कर्ष : उज्ज्वल कल की ओर

मुख्यमंत्री सुपोषण योजना केवल एक पैकेट का नाम नहीं है, बल्कि यह आने वाले कल की बुनियाद है। चित्रकूट की बरुआ आँगनबाड़ी और वाराणसी की रामनगर आँगनबाड़ी के बच्चों की खिलखिलाहट गवाही देती है कि बदलाव न सिर्फ संभव है बल्कि शुरू भी हो चुका है। एक छोटे–से स्नैक्स पैकेट में सिर्फ कैलोरी या प्रोटीन नहीं, बल्कि उन बच्चों के उजले भविष्य की संभावना, नई ऊर्जा और सपनों को पूरा करने की ताकत छिपी है। यह पैकेट उन परिवारों के लिए आश्वासन है, जो अपने बच्चों को पहले से अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी होते देख रहे हैं। आज का स्वस्थ बालक कल के मजबूत समाज और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव बनेगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना केवल आहार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को संवारने का संकल्प है। ◆

(लेखिका दंत चिकित्सक तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएच.डी. हैं)

मो. : 9205269749

युवा उद्यमी–प्रदेश की पहचान

–प्रदीप कुमार गुप्ता

उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के अनेक देशों से कहीं ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से यह युवा प्रदेश भी है। युवाओं की संख्या की दृष्टि से हमारा प्रदेश समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने अपने कार्यों से दुनिया में हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी ग्रुप कैप्टन व अंतरिक्ष यात्री डॉ. शुभान्शु शुक्ला की अन्तरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सफल यात्रा के उपरान्त सकुशल वापसी ने प्रदेश सहित देशवासियों को गर्व से भर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रदेशवासियों की भावनाओं के अनुरूप राजधानी लखनऊ में आयोजित भव्य समारोह में डॉ. शुभान्शु शुक्ला का सम्मान किया है।

किसी भी प्रदेश का विकास अपने युवाओं को साथ लिए बिना नहीं हो सकता है। युवा मन असीम ऊर्जा से भरपूर तथा कड़ी मेहनत करने में समर्थ होता है। आवश्यकता इस बात की है कि युवा ऊर्जा को सही समय पर सही दिशा और सही नेतृत्व मिल जाए। इनके बिना युवा दिग्भ्रमित हो सकते हैं। देश व प्रदेश के विकास में युवा अपना सर्वोच्च योगदान दे सकें, इसके लिए उन्हें रोजगारपरक कार्यों से जोड़ना भी अनिवार्य है, तभी वह अपनी और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवनसंग्राम में विजयी होकर उन्नति कर सकते हैं।

एक ऐसा प्रदेश, जो वर्तमान में विकास के हर क्षेत्र में नए मानक गढ़ता हुआ निरन्तर बुलन्दियों की ओर अग्रसर है, इसके युवाओं के सपनों को उड़ान देने तथा उन्हें अपना स्वयं का उद्यम स्थापित कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' (सीएम युवा) की शुरुआत की गई है। यह अभियान प्रदेश की कर्मशील आबादी 'युवा' को उद्यमी बनाने के लिए संवेदनशील सरकार की एक पहल है। योजना की सार्थकता और सफलता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 84 हजार युवा इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी शामिल है। यह अभियान पूरे देश में अभिनव व क्रान्तिकारी पहल के रूप में सामने आया है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इससे पूर्व अक्टूबर, 2024 में मुख्यमंत्री

जी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस अभियान को स्वीकृति दी गई थी। 'सीएम युवा' का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़कर प्रदेश में नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है। इससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन भी हो रहा है, क्योंकि एक युवा उद्यमी अकेले ही स्वरोजगार नहीं करता, बल्कि वह अपने साथ अन्य को भी रोजगार देता है। वह स्वयं तो अपने पांव पर खड़ा होता ही है, साथ ही दूसरों को भी सम्बल प्रदान करता है।

सीएम युवा स्कीम के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है। इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 01 लाख युवाओं को सीएम युवा स्कीम से जोड़े जाने का लक्ष्य है, इसके लिए उन्हें वित्तपोषित किया जा रहा है। सीएम युवा के अन्तर्गत पात्रता के कुछ निर्धारित मानदण्ड रखे गए हैं। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 08 उत्तीर्ण रखी गई है। इसमें भी वरीयता उन युवाओं को दिए जाने का प्राविधान है, जो इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष हैं। आवेदक को सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित होना चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से

सीएम युवा स्कीम के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है। इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 01 लाख युवाओं को सीएम युवा स्कीम से जोड़े जाने का लक्ष्य है, इसके लिए उन्हें वित्तपोषित किया जा रहा है। सीएम युवा के अन्तर्गत पात्रता के कुछ निर्धारित मानदण्ड रखे गए हैं। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 08 उत्तीर्ण रखी गई है। इसमें भी वरीयता उन युवाओं को दिए जाने का प्राविधान है, जो इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष हैं।

कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होना चाहिए।

अभियान के अन्तर्गत परियोजना लागत अथवा अधिकतम 05 लाख रुपये, जो भी कम हो, के सापेक्ष बैंक या वित्तीय संस्था से ली गई ऋण राशि पर शत–प्रतिशत ब्याज उपादान 04 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। लोन की तिथि से 06 माह की अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड) का लाभ भी युवाओं को मिल रहा है। अपना मूलधन समय से चुकाने वाले युवाओं को दूसरे चरण में साढ़े सात लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी जानना जरूरी है कि लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम 05 लाख रुपये जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की थीम हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर है। इसके लिए उद्यमी बनने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को एक एम.एस.एम.ई. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। प्राप्त आवेदनों का जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त ऑनलाइन रूप से बैंकों को प्रेषित कर दिया जाता है। बैंकों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति या वितरण की व्यवस्था है। हाल ही में 30 जुलाई को लखनऊ में आयोजित 'सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो–2025' में मुख्यमंत्री जी ने मशीनरी सप्लायर्स पोर्टल 'यूपी मार्ट' को लॉन्च किया। उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने के इच्छुक प्रदेश के लगभग 84 हजार युवाओं को सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

विगत 08 वष से प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किसी न कि नई योजना की शुरुआत की है। वर्ष 2018 में पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी 'एक जनपद एक उत्पाद' तथा वर्ष 2019 में 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान' योजना की शुरुआत की गई थी। आज यह दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश को बुलन्दियों की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इसी परम्परा पर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' की शुरुआत की। ऐसे बहुत से युवा है जो स्वयं का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होती है। उनमें

प्रतिभा, ऊर्जा तथा क्षमता तो होती है, परन्तु परिस्थितिवश धन का अभाव उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। इन सभी समस्याओं का समाधान 'सीएम युवा योजना' है। यह युवाओं के साथ ही, उनके परिवारों के सपनों को भी उड़ान देने वाली अभिनव योजना बन रही है। मुख्यमंत्री जी इस योजना के बारे में कहते हैं कि 'यह योजना युवाओं को केवल जॉब करने नहीं, बल्कि उन्हें जॉब देने की सामर्थ्य प्रदान करने का माध्यम बनी है'। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत वुड कार्निंग, वीडियोग्राफी– फोटोग्राफी, फिजियोथेरेपी, वस्त्र और कपड़ा डिजायन, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल, मेटल एण्ड एलॉय, ग्रेन मिलिंग सहित आज की मांग के अनुरूप अलग अलग क्षेत्रों में इसका लाभ युवा ले रहे हैं। ऋण प्राप्त करने वाले युवाओं में लगभग 29 प्रतिशत महिला उद्यमी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में असीमित सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इन सम्भावनाओं और क्षमताओं को वास्तविकता प्रदान करने के लिए राज्य के युवाओं के विजन को उड़ान देना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे भगीरथ प्रयासों से विगत साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश की पहचान 'उत्तम प्रदेश, एक्सप्रेस–वे प्रदेश तथा देश के विकास के ग्रोथ इन्जन' के रूप में स्थापित हुई है। अब इसे 'उद्यम प्रदेश' बनाने की दृष्टि से 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

10 लाख युवाओं को आगामी 10 वर्षों में उद्यमी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी सतत् प्रयत्नशील हैं। युवाओं को पूंजी, प्रशिक्षण तथा नए बिजनेस आइडिया प्रदान कर 'सीएम युवा' स्कीम युवाओं का मार्गदर्शन कर रही है और उन्हें उद्यमी बनने को प्रेरित भी कर रही है। सीएम युवा स्कीम प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोडकर उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यह स्कीम बड़े उद्योगों के लिए आधार का काम करने वाले एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को और विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने नवोन्मेषी कदम के रूप में जिस 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' की शुरुआत की है, वह उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम भी है। यह हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के निर्माण में भी सहायक हो रही है। युवाओं को उद्यमी बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने वाली यह योजना सिद्ध करती है कि प्रदेश सरकार को अपने युवाओं की उन्नति की न सिर्फ चिन्ता है, बल्कि सरकार इस दिशा में संवेदनशीलता व सक्रियता से आगे बढ़ भी रही है। हमारे युवा देर न करें, आज ही अपना उद्यम चुनें, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़ें और उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ चलें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में 'यही समय है, यही–सही समय है।' ◆

मो. : 7376795189

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में

पर्यटन एवं संस्कृति का हो रहा तेजी से विकास

–सुधा मिश्रा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता, पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र की पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की रही है। उनके मार्गदर्शन और विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह के प्रयास से पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र लगातार प्रभावशाली कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का कथन "प्रकृति और परमात्मा की कृपा भूमि उत्तर प्रदेश भारत के हृदय स्थल में पूरे विश्व के पर्यटकों–श्रद्धालुओं का अभिनन्दन करता है" न केवल उत्साह से परिपूर्ण है, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान वैश्विक स्तर पर पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र में स्थापित करने की मजबूत इच्छा शक्ति की झलक प्रदर्शित कर रहा है। आधुनिकता और तकनीकी के बढ़ते दखल ने पर्यटन के क्षेत्र को विस्तारित कर दिया है। लम्बी दूरियां भी अब लोगों के लिए मायने नहीं रखती। लोगों का उद्देश्य कुछ नया देखने और समझने के साथ–साथ सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में देखने और महसूस करने का है। इस बात की महत्ता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं तभी तो पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा दे रहे है। उन्होंने विजन 2047 का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इनके नेतृत्व में कई ऐसे कार्य हुए हैं और कइयों की आधारशिला भी पड़ गयी है, जिसका दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को अवश्य ही मिलेगा।

यह कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है की उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में पर्यटकों की संख्या 2375.33 लाख रही, जिसमें घरेलू पर्यटक 2339.77 लाख और विदेशी आगंतुक 35.56 लाख रहे, जिसके सापेक्ष वर्ष 2025 में जनवरी से मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़कर 10965.15 लाख हो गई। इनमें 10935.40 लाख भारतीय और 29.75 लाख विदेशी रहे। वर्ष 2017 में पंजीकृत निवेश प्रस्तावों की कुल धनराशि 758.17 करोड़ रुपए थी, जो 2025 में बढ़कर 3,646.34 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2016 में पर्यटन नीति जारी की गयी थी, किन्तु किसी भी निवेशक को सब्सिडी उपलब्ध नहीं करायी गयी वर्ष 2025 तक पर्यटन नीति 2018 एवं 2022 के अंतर्गत कुल 40.48 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2017 के पूर्व ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटरों के पंजीकरण की कोई व्यवस्था विभाग में नहीं थी। वर्ष 2022 में ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटरों के पंजीकरण की योजना लागू की गयी। अब तक प्रदेश में 157 टूर ऑपरेटरों का पंजीकरण किया गया है। वर्ष 1998 में प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना लागू की गयी थी, जिसमें केवल बड़े नगरों में ही पंजीकरण हुए। पंजीकृत इकाइयों की कुल संख्या 341 थी। वर्ष 2025 में उ.प्र. ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति 2025 जारी की गयी है। यह प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गयी है। इन सहूलियतों के जरिये सरकार न केवल आम आदमी की आमदनी में वृद्धि करने का सहयोग कर रही है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध करा रही है। सरकार ने

वर्षों में कराये गये कार्यों को पूर्ण कर जनोपयोग में लाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार विजन 2047 पर कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र में आधुनिक स्वरुप में पर्यटकों को न केवल प्रदेश में आने के लिए लुभाया जाए बल्कि आधुनिक व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध कराई जाए। इसके तहत राज्य सरकार ने पर्यटन नीति के अन्तर्गत वर्ष 2025 तक पर्यटन क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो 2047 तक बढ़कर 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

इसका उद्देश्य पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य को प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने वर्ष 2047 तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आवागमन में प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत राज्य के सभी पर्यटन गंतव्यों को 3डी मेटावर्स तकनीक से प्रचारित किया जाएगा। विभाग गंतव्यों के प्रचार–प्रसार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का

इस क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि करके अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है– वर्ष 2018 में कुल बजट रु 71702.09 लाख था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2025 में रु 202606.00 लाख है।

प्रदेश के अधिकांश पर्यटन स्थलों का कायाकल्प सरकार द्वारा किया गया है। वृद्ध एवं विपन्न कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्षों से अधिक आयु के 400 से अधिक वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया है। भारतखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय को संगीत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। 2017 से 2025 तक पर्यटन क्षेत्र में बड़े बदलाव दिखे है। राज्य योजना के अंतर्गत करायी जा रही योजनाओं की संख्या जहां वर्ष 2017 में 36 थी, वह 2025 में बढ़कर 324 हो गई। करीब 800 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017 में 05 करोड़ रुपये के प्राविधानित बजट से प्रदेश के विभिन्न जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अन्तर्गत प्रस्तावित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2025 में यह 07 करोड़ रुपये के बजट प्राविधान के अंतर्गत जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर विभिन्न जनपदों में पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये गये जो अभी निर्माणाधीन है। साथ ही, पूर्व

अधिकतम उपयोग करेगा, जिससे पर्यटक स्थलों की जानकारी आकर्षक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत की जा सके। इसके अलावा, 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी तकनीक के साथ डोम निर्मित कर पर्यटन स्थलों का ऐसा अनुभव कराया जाएगा, मानो पर्यटक स्वयं वहां मौजूद हों। सभी प्रचार–प्रसार गतिविधियां डिजिटल माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होगी। विभाग के आयोजनों में विदेशी पर्यटकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाया जा सके।

प्रदेश में ट्रैवल ट्रेड के तहत सभी जिलों में महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इस पहल के लिए वर्ष 2025 तक 2,500 लाख रुपये आवंटित करने का लक्ष्य है, जिसे 2047 तक बढ़ाकर 5,000 लाख रुपये किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अनूठी पहल की गई है। पर्यटन विभाग ने वर्ष 2025 में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में अधिक से अधिक भागीदारी दिलाने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के तहत 2025 के लिए 1500 लाख रुपये आवंटन का प्रावधान किया गया है, जिसे वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 4000 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन और पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

प्रदेश सरकार ने नैमिष, शुक्रतीर्थ, चित्रकूट, अयोध्या सहित सभी तीर्थ विकास परिषदों की महत्ता जन–जन तक पहुंचाने के लिए संबंधित क्षेत्रों में महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन आयोजनों से सरकार को मौजूदा वर्ष में 100 लाख रुपये आवंटन का लक्ष्य रखा गया है, जो 2047 तक बढ़कर 1000 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गाइडों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। योजना के तहत वर्ष 2047 तक 10,000 राज्य स्तरीय गाइड और 5,000 लोकल लेवल गाइड नियुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे पर्यटकों को बेहतर मार्गदर्शन और स्थानीय संस्कृति की गहन जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और विभाग के मंत्री जयवीर सिंह के कुशल संचालन में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने प्रदेश की छवि इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर में प्रथम रखने के लिए विजन 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है और अपने 8 वर्षों से अधिक समय में इस क्षेत्र में अप्रत्याशित कार्य किये हैं।

महाकुम्भ में विदेशी लोगों के आगमन की संख्या इस बात की साक्षी है कि सरकार आम जनता के हित में न केवल वर्तमान में तेजी से कार्य कर रही है बल्कि विजन 2047 का लक्ष्य निर्धारित करके सकारात्मक पथ पर तेजी से चलने का रोड मैप तैयार कर रखा है जो न केवल तकनीक से पूर्ण है बल्कि सभी के हितों का ध्यान रखकर के कार्य करने की योजना का निर्धारण है। मुख्यमंत्री का यह विजन इस बात की भी पुष्टि करता है कि वह प्रदेश के एक–एक व्यक्ति को न केवल समृद्ध बल्कि खुशहाल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार लगातार बड़े कार्य कर रही है। पर्यटन एवं संस्कृति भी उनमें से एक है। ◆

मो. : 8090005531

रोजगार महाकुम्भ 2025 : युवाओं के सपनों को मिली नई उड़ान

–अनिल श्रीवास्तव

भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश हमेशा से ही युवा ऊर्जा का केंद्र रहा है। यहां के लाखों युवा न केवल देश की आर्थिक रीढ़ हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बेरोजगारी की चुनौती ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने संकट खड़ा किया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त 2025 तक आयोजित 'रोजगार महाकुंभ 202' ने न केवल हजारों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति की नई दिशा भी निर्धारित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित यह तीन दिवसीय महाकुंभ नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जहां लगभग 17,000 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। यह आयोजन 'हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान' के संकल्प को साकार करने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। यह महाकुंभ न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम बना बल्कि युवाओं की प्रतिभा को पहचान देने और उन्हें उद्योग जगत से जोड़ने का सशक्त प्रयास भी साबित हुआ।

रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा कुछ निजी क्षेत्र के सहयोग से किया गया। इस महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना था, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी प्राप्त कर सकें। इस तीन दिवसीय महाकुंभ में 50 हजार से ज्यादा

युवाओं ने पंजीकरण कराया। राज्य सरकार की ओर से शुरुआत में 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह संख्या बढ़कर 17,000 के आसपास तक जा पहुंची, जो आयोजन की अपार सफलता का प्रमाण है। रोजगार महाकुंभ ने प्रदेश के युवाओं और नौकरी चाहने वालों के बीच नई उम्मीद जगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन सत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश अब 'रोजगार देने वाला राज्य' बन चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले जहां युवा पलायन करने को मजबूर होते थे, वहीं अब वे न केवल स्वयं रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान करने का माध्यम बन रहे हैं। यह महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मिशन रोजगार' अभियान का हिस्सा भी था, जिसे उत्तर प्रदेश को वैश्विक टैलेंट हब बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल कहा जा सकता है। रोजगार महाकुंभ में 100 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल हुईं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, वाधवानी एआई, अमेजन एडब्ल्यूएस, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख थीं। इन कंपनियों ने एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में 50,000 से अधिक नौकरियां और 15,000 अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराए। महाकुंभ में सबसे अधिक अवसर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में दिखाई दिए।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए इस विशाल आयोजन में 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट–ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। पंजीकरण 'रोजगार संगम' पोर्टल (rojgaarsangam.up.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया गया, जिससे साक्षात्कार की प्रक्रिया बेहद सुगम रही। पहले दिन उद्घाटन के साथ ही महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ी। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित किए। खास बात यह रही कि पहले दिन ही लगभग 50,000 युवा महाकुंभ में पहुंचे, जिससे थोड़ी देर के लिए कुछ अव्यवस्था भी हुई किंतु शासन और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल टोकन सिस्टम लागू कर स्थिति को संभाल लिया। महाकुंभ के दूसरे दिन 7,479 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें 6,947 को भारतीय कंपनियों और 532 को यूएई

की 22 कंपनियों में नौकरी मिली जबकि तीसरे दिन 7,600 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले, जिससे रोजगार प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 17,000 के आसपास तक जा पहुंची। आयोजन से जुड़े शासन के अधिकारियों ने एक ही जगह पर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने को 'बड़ी सफलता' करार दिया। गौरतलब बात यह है कि इस महाकुंभ में भारतीय कंपनियों की ओर से चयनित युवाओं को जहां 2–30 लाख से 7 लाख रुपये वार्षिक का ऑफर दिया गया वहीं दुबई की कंपनियों ने 6 लाख रुपये वार्षिक तक का ऑफर दिया है।

रोजगार महाकुंभ की सफलता आंकड़ों में स्पष्ट झलकती है। तय लक्ष्य से 69 प्रतिशत अधिक युवाओं को रोजगार मिला, जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले आठ वर्षों में योगी सरकार ने 8–5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दीं और 'सीएम युवा उद्यमी योजना'

के तहत युवाओं को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। यह महाकुंभ न केवल रोजगार प्रदान करने वाला था, बल्कि युवाओं को न्यूनतम वेतन गारंटी का आश्वासन भी दिया गया, जो उत्तर प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बनाने की दिशा में कदम है। महाकुंभ को लेकर युवाओं की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही।

विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए युवाओं ने इस मंच को अपने सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर माना। एक्स पर कुछ युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। एक यूजर ने लिखा, ''रोजगार महाकुंभ ने मेरे जैसे कई युवाओं को नई दिशा दी।'' एक अन्य यूजर ने कहा, ''मुझे जर्मनी में नौकरी का ऑफर मिला! यह मेरे लिए अविश्वसनीय है। योगी सरकार को धन्यवाद।'' एक चयनित अभ्यर्थी ने कहा, ''यह मंच मेरे सपनों को साकार करने का माध्यम बना।'' कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आयोजन युवाओं के बीच विश्वास बढ़ाने वाला साबित हुआ। रोजगार महाकुंभ 2025 में भाग लेने वाले युवाओं के अनुभवों से स्पष्ट है कि यह आयोजन न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करने में सफल रहा, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास और नई स्किल्स का विकास भी किया। अधिकांश युवाओं ने इसे एक ऐतिहासिक पहल माना। चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव इस बात के प्रमाण हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खास बात यह है कि महाकुंभ में भाग लेने वाले युवाओं को सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद करने का मौका मिला। इससे उन्हें न केवल नौकरी पाने का अवसर मिला बल्कि उद्योग की जरूरतों और वर्तमान समय की मांगों को समझकर खुद को उसके अनुरूप तैयार करने का अनुभव भी प्राप्त हुआ।

आयोजन के दौरान पहले दिन भारी भीड़ के कारण हुई कुछ अव्यवस्थाओं और दूर–दराज से आने वाले युवाओं की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में जिला स्तर पर ऐसे मेले आयोजित होंगे। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक, भविष्य में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) योजना के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की योजना तैयार की जा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हो सकें। रोजगार महाकुंभ 2025 ने साबित कर दिया कि सही दिशा और संकल्प से बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान संभव है। यह न केवल युवाओं के लिए सुनहरा अवसर था, बल्कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मजबूत कदम भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में, ''यह महाकुंभ युवा ऊर्जा को नई उड़ान देगा।'' आने वाले समय में ऐसे और आयोजनों से उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रोजगार महाकुंभ की सफलता न केवल आंकड़ों की, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों की जीत है। यह आयोजन सिर्फ रोजगार मेला नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमताओं और सपनों को पंख देने वाला महोत्सव साबित हुआ है। ◆

मो. : 9935097410

उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रतिबद्ध है योगी सरकार

–डॉ. अजय कुमार मिश्रा

किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के पीछे कई महत्वपूर्ण निर्णय और कार्यविधि का तय समय पर पूरा होना आवश्यक होता है। देश के कई बड़े राज्यों में आर्थिक विकास के पीछे कई मुख्य बिन्दुओं के अलावा उस प्रदेश में कम्पनियों द्वारा निवेश का होना रहा है। बात जब उत्तर प्रदेश की होती है तो विगत आठ वर्ष में प्रदेश की जो तस्वीर वैश्विक स्तर पर अब विद्यमान हुई है वह कई दशकों में भी नहीं हो पायी थी। प्रदेश हमेशा से कई ऐसी बातों के लिए जाना जाता था, जिससे मुक्ति मिलना आसान नहीं था। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की छवि उन बातों में तेजी से परिवर्तित होने लगी और आज स्थिति यह है कि सभी उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करना चाह रहे हैं। शांति, सुरक्षा और विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुशल नेतृत्व और जमीनी कार्यविधि का प्रभाव न केवल आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है, बल्कि प्रदेश की ख्याति भी तेजी से वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक विभाग के मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने ऐतिहासिक पहल करके कई बड़े बदलाव किये, जिससे कंपनियां और संस्थान उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। इसका सीधा लाभ कई रूपों में यहाँ प्राप्त हो रहा है। इस बात को अग्रलिखित आंकड़े भी सहयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश करके कार्य करने के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 20 हजार से अधिक एम.ओ.यू साइन किये गये हैं। साइन किये गये एम.ओ.यू के जरिये कुल 37.38 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में होना आपेक्षित है। 12 लाख करोड़ से अधिक लागत की 16,000 से अधिक परियोजनाओं का भूमिपूजन समारोह भी किया जा चुका है। वर्ष 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश को शीर्ष उपलब्धि प्राप्त है। वर्ष 2022, 2023 और 2024 में लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में भी प्रदेश को उपलब्धि प्राप्त है। वर्ष 2021 में प्रदेश गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है और निर्यात तैयारी सूचकांक में दूसरे स्थान पर है जो इसे

भारत में सबसे सुरक्षित और निवेश–अनुकूल स्थलों में से एक बनाता है। ये उपलब्धियां कठिन परिश्रम और सही समय पर सही निर्णय को दर्शाती है। इन्वेस्ट यूपी पहल को एम.ओ.यू. कार्यान्वयन, निवेश अनुमोदन और परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए उन्नत किया जा रहा है। निवेश सारथी परिचालन–एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत 118 उद्यमी मित्र भी शामिल हुए। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पाँच क्षेत्रीय डेस्क बनाए गए हैं ताकि केंद्रित सुविधा प्रदान की जा सके। नए निवेश आकर्षित किए जा सकें और निवेशकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायता के लिए चार समर्पित देश डेस्क स्थापित किए गए है।

निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्र–एकल– खिड़की निकासी प्रणाली का शुभारम्भ किया गया है। यह 43 विभागों की सेवाओं को एकीकृत करता है, अनुमोदन, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए 520 से अधिक सेवाएँ प्रदान करता है। इसकी 97 प्रतिशत से अधिक की निपटान दर है। 18 लाख से अधिक अनुमोदन डिजिटल रूप से जारी किए गए हैं, 'ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली' चालू है। नियामक अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए 65 विभागों में 4,675 अनुपालन कम किए गए हैं, 577 अनुपालनों को गैर–अपराधीकरण श्रेणी में लाया गया है, 948 अधिनियमों/विनियमों/नियमों आदि को निरस्त किया गया है। व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2022–352 अनुशंसित सुधारों का 100 प्रतिशत कार्यान्वयन किया गया है। निवेश मित्र 3.0 का विकास प्रक्रिया में जिससे कम समय में अधिक कार्य हो सकेगा। निवेशकों को एक एकीकृत निकासी प्रणाली प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) के साथ एकीकरण भी किया जा रहा है।

निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्र–एकल– खिड़की निकासी प्रणाली का शुभारम्भ किया गया है। यह 43 विभागों की सेवाओं को एकीकृत करता है, अनुमोदन, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए 520 से अधिक सेवाएँ प्रदान करता है, इसकी 97 प्रतिशत से अधिक की निपटान दर है, 18 लाख से अधिक अनुमोदन डिजिटल रूप से जारी किए गए हैं, 'ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली' चालू है। नियामक अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए 65 विभागों में 4,675 अनुपालन कम किए गए हैं, 577 अनुपालनों को गैर–अपराधीकरण श्रेणी में लाया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मेजर डिसिजन लिए है। भारत में अपनी तरह के पहले कदम के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए समर्पित नीति 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)', 'विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति' पेश की है। निवेश आकर्षित करने के लिए 30 से अधिक क्षेत्र–विशिष्ट और अनुकूलित नीतियाँ तैयार की गई हैं प्रमुख क्षेत्रों में आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, रक्षा और एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, कपड़ा, एमएसएमई आदि शामिल हैं। 2024 में घोषित प्रमुख नई नीतियाँ–सेमीकंडक्टर नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, बायो–प्लास्टिक नीति, मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति और एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, साथ ही प्रतिस्पर्धी वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) है।

राज्य पारिस्थितिकी तंत्र की माँगों के अनुरूप और अधिक लाभदायक निवेश परिस्थितिकी तंत्र की दिशा में नीतियों में संशोधन प्रस्तावित करने पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करता है। विचाराधीन उल्लेखनीय नीतियों में IIEPP 2022, FDI/FCI नीति और EV नीति शामिल हैं। राज्य उभरते क्षेत्रों में निवेश को मजबूत करने के लिए नई नीतियां शुरू करने पर भी विचार कर रहा है। राज्य ने विश्वस्तरीय

बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया है, जिसमें ऐतिहासिक गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली पर देश की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना भी शामिल है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (NW-1) के रूप में जाना जाता है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक है। वाराणसी और हल्दिया के बीच लगभग 1,100 किलोमीटर का खंड पहले से ही चालू है। राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर परिचालन सुविधाओं में वाराणसी में एक मल्टी–मॉडल टर्मिनल और गाजीपुर, राजघाट, रामनगर (वाराणसी) व प्रयागराज में फ्लोटिंग टर्मिनल शामिल है। इसके अतिरिक्त, दादरी में एक मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बोराकी में एक मल्टी–मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) का विकास किया जा रहा है ताकि लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा सके। उत्तर प्रदेश में सड़क और रेलवे का सबसे बड़ा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक विभाग के मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने ऐतिहासिक पहल करके कई बड़े बदलाव किये, जिससे कंपनियां और संस्थान उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। जिसका सीधा लाभ कई रूपों में यहाँ प्राप्त हो रहा है। इस बात को अग्रलिखित आकड़े भी सहयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश करके कार्य करने के लिए विभिन्न कंपनियों द्वारा कुल 20 हजार से अधिक एम.ओ.यू साइन किये गये है। साइन किये गये एम.ओ.यू के जरिये कुल 37.38 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में होना आपेक्षित है। 12 लाख करोड़ से अधिक लागत की 16,000 से अधिक परियोजनाओं का भूमिपूजन समारोह भी किया जा चुका है।

नेटवर्क, एक्सप्रेसवे, 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 12 घरेलू हवाई अड्डे हैं और यह भारत के समर्पित औद्योगिक माल ढुलाई गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से स्थित है, जो विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 91.35 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2025 में किया गया। 6 नए एक्सप्रेसवे और नोएडा के जेवर में 5वें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में अग्रणी है, आवश्यक और अतिरिक्त डेटा परतों के लगभग पूर्ण एकीकरण के साथ, 2,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है, 26 से अधिक नियोजन ऐप विकसित किए गए हैं और एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि खरीद केंद्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के

अनुरूप, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की योजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के अंतर्गत 6 नोड्स–लखनऊ, कानपुर, झाँसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में बनाई जा रही है। 2,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। राज्य में पहले से ही डीआरडीओ ब्रह्मोस, अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस (500 एकड़, कानपुर), भारत डायनेमिक्स और अन्य प्रमुख कंपनियाँ मौजूद हैं।

इन्वेस्ट यू.पी. की मजबूत टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विभाग के मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नंदी' के नेतृत्व में श्री शशि प्रकाश गोयल, श्री अलोक कुमार, श्री विजय किरण आनंद, श्री शशांक चौधरी और श्री प्रथमेश कुमार और उनकी टीम लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य यहाँ की आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करना और नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इन्वेस्ट यू.पी. के प्राथमिकता वाले क्षेत्र का निर्धारण करके अपने लक्ष्य को विस्तारित भी कर दिया है इनमें पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और वस्त्र मुख्य फोकस क्षेत्र बने हुए हैं। समर्पित नीतियों और भदोही कालीन और वाराणसी रेशम जैसे विश्व–प्रसिद्ध समूहों के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। उच्च तकनीक और उभरते क्षेत्र : उत्तर प्रदेश खुद को सेमीकंडक्टर, आईटी और आईटीईएस, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसे एचसीएल–फॉक्सकॉन, टार्क सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, सैमसंग, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ओप्पो और वीवो जैसी समर्पित नीतियों और प्रमुख परियोजनाओं का समर्थन भी प्राप्त है। इन आंकड़ों और उपलब्धियों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रदेश की मजबूत निवेश नीति और त्वरित कार्य प्रणाली अवश्य ही प्रदेश के विकास में सहायक होगी। ◆

मो. : 9335226715

विकसित भारत की आधार भूमि उत्तर प्रदेश

—डॉ दीपक कोहली

उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति का सार है और उसकी जनशक्ति का जीवंत उदाहरण भी। यह भूमि वह है जहाँ भारत का इतिहास रचा गया, जहाँ परंपरा ने आधुनिकता को दिशा दी और जहाँ हर युग में परिवर्तन की लहरें उठीं। जब भारत स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर अग्रसर है, तब उत्तर प्रदेश का विकसित होना केवल एक राज्य का विकास नहीं, बल्कि राष्ट्र के संपूर्ण पुनरुत्थान का प्रतीक है। विकसित उत्तर प्रदेश का स्वप्न वह दृष्टि है जो भविष्य के भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध, तकनीकी और सांस्कृतिक दृष्टि से सशक्त बनाएगा। यह वह यात्रा है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी है, हर गाँव की गूंज है और हर युवा की आकांक्षा है।

बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जिस गति से विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं, उसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। कभी पिछड़ेपन और अव्यवस्था के लिए चर्चित यह प्रदेश अब योजनाबद्ध नीति, दृढ़ नेतृत्व और सामूहिक संकल्प के बल पर नए युग की शुरुआत कर चुका है। गाँवों से लेकर शहरों तक सड़कों का जाल बिछ चुका है, बिजली की पहुंच अंतिम घर तक हो चुकी है, औद्योगिक निवेश का माहौल बन चुका है और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएँ व्यापक रूप से सुलभ हुई हैं। यह केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का परिणाम भी है। आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक परिवर्तन की इस धारा का हिस्सा बन चुका है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर विस्तार की दिशा में बढ़ रही है। वर्तमान में यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग नौ प्रतिशत योगदान दे रही है और 2047 तक इसे छह ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। यह कोई असंभव स्वप्न नहीं, क्योंकि इसकी नींव पहले से रखी जा चुकी है। औद्योगिक नीति, निवेशक–अनुकूल वातावरण, डिफेंस कॉरिडोर, स्टार्टअप संस्कृति और "एक जिला एक उत्पाद" जैसी योजनाओं ने प्रदेश को उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ाया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर उद्योगों, नवाचार और सेवा क्षेत्र के नए केंद्र बन चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस–वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे जैसे मार्ग अब केवल सड़कें नहीं, बल्कि विकास की धमनियाँ हैं जो प्रदेश के प्रत्येक कोने को एक–दूसरे से जोड़ रही हैं।

कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश की आत्मा है। राज्य के लगभग सत्तर प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हैं और इसलिए विकसित उत्तर प्रदेश का आधार भी ग्रामीण समृद्धि में ही है। नई कृषि तकनीकों, जल प्रबंधन, जैविक खेती, फसल विविधीकरण और बाजार से सीधे जुड़ाव ने किसानों की स्थिति में सुधार लाना शुरू कर दिया है। डिजिटल मंडियों ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सहायता की है और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों ने उनके उत्पादों को नई पहचान दी है। भविष्य का लक्ष्य यह है कि किसान केवल उत्पादक न रहकर उद्यमी बने, जो अपनी फसल का मूल्य स्वयं निर्धारित कर सके और वैश्विक बाजार से सीधे जुड़ सके। ऐसा होते ही उत्तर प्रदेश केवल खाद्यान्न उत्पादक नहीं रहेगा, बल्कि खाद्य निर्यातक राज्य बनेगा।

शिक्षा किसी भी समाज के भविष्य का आधार है। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहलें की हैं। प्राथमिक स्तर पर मिशन प्रेरणा, उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, कौशल विकास योजनाएँ और नई शिक्षा नीति के अनुरूप संस्थानों का पुनर्गठन–ये सभी प्रयास युवा पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बना रहे हैं। आज राज्य के हर जिले में उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ रही है। तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण हो रहा है ताकि छात्र केवल पढ़े–लिखे नहीं, बल्कि कुशल भी हों। युवाओं को स्टार्टअप और इनोवेशन की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। 2047 का उत्तर प्रदेश वह होगा जहाँ प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर, सक्षम और नवाचार में अग्रणी होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी राज्य ने लंबी दूरी तय की है। जहाँ कभी स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित थीं, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। टेलीमेडिसिन, ई–संजीवनी और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने आम नागरिक को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। मातृ–शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता अभियान ने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। 2047 तक यह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक बुनियादी चिकित्सा से वंचित न रहे और हर गांव–शहर में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत हो।

उत्तर प्रदेश के विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा और पर्यावरण का संतुलन। प्रदेश ने सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाया है ताकि ऊर्जा उत्पादन टिकाऊ और स्वच्छ बन सके। बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े सौर ऊर्जा पार्क बन रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में छोटे सोलर ग्रिड लगाए जा रहे हैं। साथ ही गंगा और यमुना की स्वच्छता के लिए अभियान जारी हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ–साथ चल सकें। हरित वृक्षारोपण अभियान और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि 2047 तक उत्तर प्रदेश एक पर्यावरण–संवेदनशील प्रदेश के रूप में स्थापित हो।

पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने नया इतिहास रचा है। काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, मथुरा–वृंदावन का विकास, सारनाथ और कुशीनगर का वैश्विक बौद्ध सर्किट में जुड़ाव–इन सबने प्रदेश को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इसके अलावा वाराणसी की देव दीपावली, अयोध्या की दीपोत्सव, प्रयागराज का कुंभ, आगरा और लखनऊ का सांस्कृतिक वैभव–इन सभी ने वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की पहचान मजबूत की है। 2047 तक यह राज्य विश्व के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

अधोसंरचना विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आज भारत के अग्रणी राज्यों में है। एक्सप्रेस–वे नेटवर्क, मेट्रो सेवाएँ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों ने इस राज्य को निवेश और व्यापार के लिए उपयुक्त बनाया है। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बनने जा रहा है, जिससे न केवल नोएडा क्षेत्र, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई उड़ान मिलेगी। वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो रेल सेवा से शहरी यातायात सुविधाजनक हो गया है। भविष्य का उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा जहाँ सड़क, रेल, जल और वायु सभी परिवहन साधन एक–दूसरे से जुड़े होंगे।

शहरीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और झांसी जैसे शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल प्रशासन, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ जल और हरित परिवहन ने शहरी जीवन को अधिक सहज बनाया है। भविष्य में यह लक्ष्य है कि छोटे कस्बों को भी विकसित शहरी इकाइयों के रूप में तैयार किया जाए ताकि जनसंख्या का दबाव केवल बड़े शहरों पर न पड़े। "स्वच्छ, सुरक्षित और स्मार्ट" शहर विकसित उत्तर प्रदेश की पहचान होंगे।

विकास की असली शक्ति सुशासन में होती है। उत्तर प्रदेश ने शासन को पारदर्शी, तकनीक–संचालित और जनकेंद्रित बनाया है। ई–गवर्नेंस, डिजिटल पोर्टल,

ऑनलाइन शिकायत निवारण और पारदर्शी भर्ती प्रणाली से नागरिकों में विश्वास बढ़ा है। अब शासन केवल आदेश देने वाला तंत्र नहीं, बल्कि संवाद और सेवा का माध्यम बन चुका है। यही लोकतंत्र की वास्तविक भावना है, जो 2047 तक उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक मॉडल बना सकती है।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला योजना और स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता दी है। आज महिलाएँ उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और राजनीति–हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। 2047 का उत्तर प्रदेश ऐसा होगा जहाँ नारी केवल सहभागी नहीं, बल्कि नीति–निर्माता होगी।

समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के बिना कोई भी विकास पूर्ण नहीं होता। उत्तर प्रदेश ने गरीबों के लिए आवास, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्तियाँ और स्वरोजगार योजनाएँ शुरू की हैं। उद्देश्य यही है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे वह शहर में हो या गाँव में। समावेशी विकास ही सच्चा विकास है।

इन उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियाँ भी हैं। बड़ी जनसंख्या, क्षेत्रीय असमानता, पर्यावरणीय दबाव, रोजगार सृजन और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन–ये वे क्षेत्र हैं जिन पर निरंतर ध्यान देना होगा। परंतु इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के लोगों का परिश्रम, युवा शक्ति का उत्साह और नेतृत्व का दूरदृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण मिलकर इन कठिनाइयों को परास्त कर सकते हैं। 2047 का उत्तर प्रदेश वह होगा जहाँ हर नागरिक शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा। जहाँ किसान तकनीक से जुड़ा होगा, उद्योग विश्वस्तरीय होंगे, महिलाएँ नेतृत्व करेंगी, और प्रशासन पारदर्शी होगा। गाँवों में विकास की गूँज होगी, शहरों में स्वच्छता और ऊर्जा का प्रकाश होगा, और पर्यावरण के साथ संतुलित प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत होगा। यह वह प्रदेश होगा जहाँ परंपरा और प्रगति एक साथ चलेंगी, जहाँ धर्म, विज्ञान और संस्कृति का सुंदर संगम होगा।

विकसित उत्तर प्रदेश का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की उन्नति भी है। जब हर व्यक्ति अपने जीवन में अवसर और सम्मान पाएगा, जब शिक्षा और स्वास्थ्य हर घर तक पहुँचेंगे, जब शासन जनता का मित्र बनेगा–तभी यह स्वप्न पूर्ण होगा। यह यात्रा लंबी है, लेकिन संकल्प दृढ़ है। 2047 का सूर्योदय एक ऐसे उत्तर प्रदेश का स्वागत करेगा जो आत्मनिर्भर, समृद्ध, शिक्षित, स्वच्छ, सशक्त और सर्वसमावेशी होगा। यही विकसित उत्तर प्रदेश की सच्ची परिभाषा होगी–एक ऐसा प्रदेश जो न केवल भारत का गौरव बने, बल्कि विश्व के लिए आदर्श बने। ◆

(लेखक–लोक निर्माण विभाग में विशेष सचिव हैं)

मो. : 6389005559

रामायण सर्किट : अयोध्या से जनकपुर धाम की यात्रा होगी आसान

–यशोदा श्रीवास्तव

योगी सरकार यूपी को टूरिस्ट हब बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश में 11 ईको टूरिज्म स्थलों का ईको टूरिज्म आईकान के रूप में विकसित करने की पर्यटन विभाग की योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टूरिस्ट विजन का हिस्सा है। इन टूरिस्ट स्थलों को उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विश्व स्तरीय टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

योगी के सपनों के अनुरूप जब ये टूरिस्ट स्थल पूर्णतया विकसित हो जाएंगे तब यहां प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक ईको फ्रेंडली का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप यूपी में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ईको टूरिज्म स्थलों को टूरिस्ट हब के रूप में भी विकसित किया जाय।

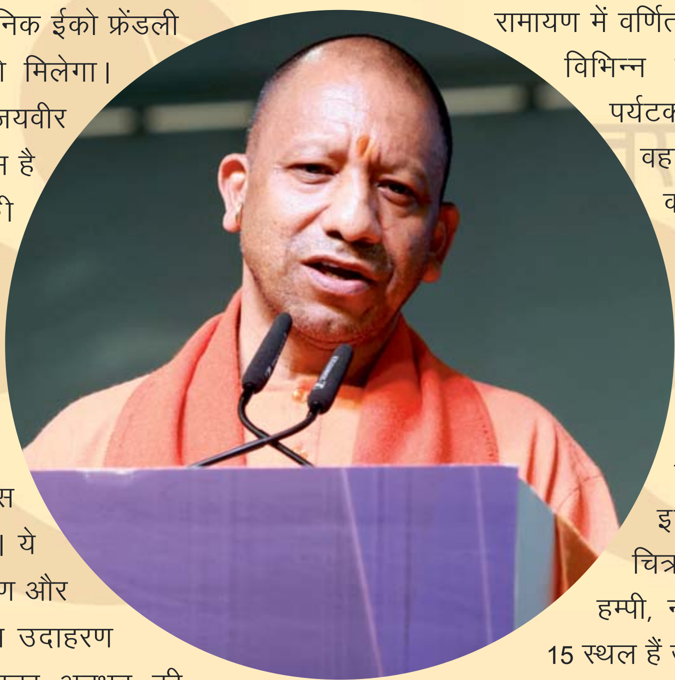

पर्यटन विभाग इस दिशा में सक्रिय हो चुका है। ये टूरिस्ट स्थल पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास की अनुपम उदाहरण होंगे जहां पर्यटकों को बेहतर अनुभव की अनुभूति स्वतरू होगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि यूपी ईटीडीबी की इस नई पहल के तहत अयोध्या, बलिया, बाराबंकी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, सीतापुर, महराजगंज, ललित पुर, कुशीनगर और मिल्कीपुर (अयोध्या) तक ईको टूरिज्म परिसंपत्तियों का विस्तार किया गया है। ये स्थल देश के सर्वोत्तम और पूर्णतया विकसित ईको टूरिज्म आईकान की दिशा में अग्रसर हैं। ये टूरिस्ट स्थल केवल पर्यटकीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं होंगे, निदेशक पर्यटन (ईको) की मानें तो यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार,प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी जब जब टूरिस्ट और धार्मिक स्थलों के संपूर्ण विकास की बात करते हैं तब तब प्रभु श्री राम के भक्तों में यह आस जगना स्वाभाविक है कि अब रामायण सर्किट परियोजना पर भी तेजी से काम शुरू होगा और हम राम नगरी के साथ माता सीता के मायके जनकपुर धाम का भी दर्शन आसानी से कर सकेंगे।

रामायण सर्किट भारत सरकार की एक पहल है जो रामायण में वर्णित भगवान राम से जुड़े देश के विभिन्न स्थलों को धार्मिक और पर्यटकीय दृष्टि से विकसित कर वहां तक लोगों की पहुंच आसान करेगा। यह पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है। इसका मात्र उद्देश्य श्रद्धालुओं और टूरिस्टों को धार्मिक और पर्यटकीय स्थलों की यात्रा का अवसर प्रदान करना है। इसमें अयोध्या, सीतामढ़ी, चित्रकूट, रामेश्वरम, भद्राचलम, हम्पी, नासिक और महेंद्र गिरी जैसे 15 स्थल हैं जो विभिन्न प्रदेशों में स्थित है।

रामायण सर्किट का विस्तार सीता मढ़ी (बिहार) तक हो जाने से लोगों को माता सीता के मायके जनकपुर धाम का दर्शन आसान होगा। सीता मढ़ी से जनकपुर का मार्ग आसान है। यहां से दूरी भी कम है।

मिथिला संस्कृति के अनुसार ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जनकपुर से माता सीता के ससुराल अयोध्या को दो ट्रकों में भरकर सौगात भेजे गए थे। मान्यता है कि जब बेटी अपने ससुराल के नए घर में प्रवेश करती है तो उसके मायके से कुछ सगुन भेजे जाते हैं। इसी मान्यता के

तहत अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जनकपुर से ट्रकों से भारी भरकम सौगात भेजे गए थे। अयोध्या और जनकपुर के कनेक्शन के कारण ही राम मंदिर को लेकर जितना उत्साह भारत के कोने कोने में था उससे जरा भी कम नेपाल में नहीं था। अयोध्या के नवनिर्मित भव्य मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शनार्थ नेपाल के लोगों के जाने का क्रम जारी है।

कभी भारत का ही हिस्सा रहा जनकपुर धाम प्राचीन काल में विदेह राज्य की राजधानी थी। भगवान श्रीराम से विवाह के पहले सीता ने ज्यादातर समय यहीं व्यतीत किया था। जानकी मंदिर साल 1911 में बनकर तैयार हुआ था। करीब 4860 वर्ग फीट में फैले इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कहानी यह है कि 'पहले यहां जंगल हुआ करता था, जहां शुर किशोर दास नामक रिशी तपस्या–साधना करने पहुंचे थे। यहां रहने के दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली थी, जो सोने की थी। उन्होंने ही इसे वहां स्थापित किया था।

योगी के सपनों के अनुरूप जब ये टूरिस्ट स्थल पूर्णतया विकसित हो जाएंगे तब यहां प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक ईको फ्रेंडली का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप यूपी में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ईको टूरिज्म स्थलों को टूरिस्ट हब के रूप में भी विकसित किया जाय।

टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु एक बार वहां गई थीं। उन्हें कोई संतान नहीं था। वहां पूजा के दौरान उन्होंने यह मन्नत मांगी थी कि अगर भविष्य में उन्हें कोई संतान होता है तो वो वहां मंदिर बनवाएंगी। संतान की प्राप्ति के बाद वो वहां लौटीं और साल 1895 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ जो 16 साल में पूरा हुआ। बताते हैं कि उस समय इसके निर्माण पर कुल नौ लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहते हैं। 1967 से ही इस मंदिर में 12 महीने अखंड कीर्तन चलता रहता है।24 घंटे सीता–राम नाम का जाप यहां लोग करते हैं।

अंग्रेजी शासन के वक्त एक समझौते में नेपाल को मेची नदी के पूर्व और महाकाली नदी के पश्चिम के बीच का तराई क्षेत्र दिया गया था। इस तरह मिथिला का एक बड़ा भूभाग नेपाल में शामिल कर दिया गया, जिसमें जनकपुर भी था। राजा जनक के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था।राजा जनक की पुत्री सीता जिन्हें जानकी भी कहते हैं, उनके नाम पर इस मंदिर का नामकरण हुआ था। जानकी मंदिर में तीर्थ यात्री न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। यहां यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी तीर्थ यात्री आते है। मंदिर में मां सीता की मूर्ति अत्यंत प्राचीन है जो 1657 के आसपास की बताई जाती है।

अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने के लिए सीएम योगी ने रामायण सर्किट का शुभारंभ किया है। राम और सीता से जुड़े भारत और नेपाल के इन धार्मिक

कभी भारत का ही हिस्सा रहा जनकपुर धाम प्राचीन काल में विदेह राज्य की राजधानी थी। भगवान श्रीराम से विवाह के पहले सीता ने ज्यादातर समय यहीं व्यतीत किया था। जानकी मंदिर साल 1911 में बनकर तैयार हुआ था। करीब 4860 वर्ग फीट में फैले इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कहानी यह है कि 'पहले यहां जंगल हुआ करता था, जहां शुर किशोर दास नामक रिशी तपस्या–साधना करने पहुंचे थे। यहां रहने के दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली थी, जो सोने की थी। उन्होंने ही इसे वहां स्थापित किया था।

स्थलों तक आसानी से पंहुचने के लिए एसी बस भी चलाई गई है। इतना ही नहीं जनकपुर धाम तक भारत द्वारा ट्रेन भी चलाई गई है जो जयनगर से चलेगी। इसके लिए भारत से नेपाल का रेल समझौता हुआ है। 2019 में कोंकण रेलवे कारपोरेशन महाराष्ट्र ने 84 करोड़ 65 लाख रूपये में चार बोगी और इंजन समेत दो अदद डीएमयू सवारी गाड़ी नेपाल को उपलब्ध करा दिया है। बताते हैं कि भारतीय रेल चालकों द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनक पुर धाम तक पंहुचाई गई रेल गाणी अभी संचलन की प्रक्रिया में है।

नेपाल में इस रूट पर सर्वप्रथम रेल संचलन के पीछे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राम की अयोध्या और माता सीता के जनकपुर धाम तक जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना रामायण सर्किट का सपना साकार करना है। ◆

पं. दीनदयाल उपाध्याय

–डॉ. सौरभ मालवीय

"भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है, इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा।" ये शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हैं, जिन्हें जनसंघ के राष्ट्रजीवन दर्शन का निर्माता माना जाता है। वे मानते थे कि राजनीतिक जीवनदर्शन का पहला सूत्र संस्कृतिनिष्ठा है।

वास्तव में भारतीय 'वसुधैव कुटुम्बकम्' में विश्वास रखते हैं। यह हमारा मूल मंत्र है। इसके अनुसार भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। इसी कारण भारत विश्व गुरु माना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। एकात्म मानववाद के रूप में उन्होंने अपने विचारों की व्याख्या की तथा एक राष्ट्रवादी दर्शन के रूप में इसे स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने एकात्म मानववाद दर्शन को जन–जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। (वे न केवल वैचारिक चुनौतियों के प्रति सजग थे, परन्तु उन चुनौतियों का सामना राष्ट्रवाद के माध्यम से करने को दृष्ट संकल्प भी प्रतीत होते हैं।) भारत जैसे विशाल एवं सर्वसाधन सम्पन्न राष्ट्र जिसने अपनी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर सम्पूर्ण विश्व को अपने ज्ञान पुंज से आलोकित कर मानवता का पाठ पढ़ाया तथा विश्व में जगतगुरु के पद पर प्रतिस्थापित हुआ, ऐसे विशाल राष्ट्र के पराधीनता के कारणों पर दीनदयाल जी का विचार और स्वाधीनता पश्चात् समर्थ और सशक्त भारत बनाने में उनके विचार प्रेरणास्पद हैं।

प्रसिद्ध विचारक और प्रख्यात पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन में से अनेक वर्षों तक आर्गेनाइजर, राष्ट्रधर्म, पांचजन्य में तत्कालीन राजनीतिक–आर्थिक घटनाक्रम पर गम्भीर विवेचनात्मक टिप्पणियां लिखते रहे। यद्यपि विषय तत्कालीन होता या, तो भी उस पर दीनदयाल जी की टिप्पणी सामयिक के साथ–साथ बहुधा दीर्घकालीन या स्थायी महत्व की भी होती थी।

भारत को एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, इस बात को मानते हुए लेख में वे स्पष्टता के साथ लिखते कि फिर से वापस नहीं लौटा जा सकता। अतः दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दासता के काल में आगामी विकृतियों को हम दूर करने का प्रयास न करें। वे लिखते हैं– अतः हमको सावधानी रखनी होगी कि हम अपने जर्जर शरीर को रोगमुक्त करके जब तक स्वस्थ होकर खड़े हों, तब तक बीच में ही कोई हमारे ऊपर हावी न हो जाएं। संसार के अनेक देशों के साथ हमारे संबंध रहे हैं। हमें अनेक पुराने अप्राकृतिक संबंध तोड़ने पड़ेंगे, नवीन निर्माण करने होंगे।

अपने एकात्म मानववाद दर्शन के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्र की चिति की अवधारणा को व्याख्यायित करने का निरंतर प्रयास किया। दीनदयाल जी चिति को राष्ट्र के अस्तित्व का मुख्य आधार मानते थे। उनका मानना था कि भारत को बलशाली और वैभवशाली तभी बनाया जा सकता है, जब भारत की चिति को समझा जा सके। चिति को बिना

समझे राष्ट्र को समझना दुष्कर है तथा बिना राष्ट्र को समझे इसे बलशाली और वैभवशाली बनना असम्भव है। इस प्रश्न को रेखांकित करते हुए वे लिखते हैं–

हमारे राष्ट्र जीवन की चिति क्या है? हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है? इस स्वरूप की व्याख्या करना कठिन है उसका तो साक्षात्कार ही संभव है, किंतु जिन महापुरूषों ने राष्ट्रात्मा का पूर्ण साक्षात्कार किया, जिनके जीवन में चिति का प्रकाश उज्ज्वलतम रहा है। उनके जीवन की ओर देखने से, उनके जीवन की क्रियाओं और घटनाओं का विश्लेषण करने से, हम अपनी चिति के स्वरूप की कुछ झलक पा सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आनेवाली राष्ट्र पुरुषों की परंपरा के भीतर छिपे हुए सूत्र को यदि हम ढूंढें, तो संभवतया चिति के व्यक्त परिणाम की मीमांसा से उसके अव्यक्त कारण की भी हमें अनुभूति हो सके। जिन महान् विभूतियों के नाम स्मरण मात्र से हम अपने जीवन में दुर्बलता के क्षणों में शक्ति का अनुभव करते हैं, कायरता की कृति का स्थान वीर व्रत ले लेता है, उनके जीवन में कौन सी बात है, जो हममें इतना सामर्थ्य भर देती है? कौन सी चीज है जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं? हमारा मस्तक श्रद्धा से किसके सामने नत होता है और क्यों? वह कौन सा लक्ष्य है, जिसके चारों ओर हमारा राष्ट्र जीवन घूमता आया है? अपने राष्ट्र के किस तत्व को बचाने के लिए हमने बड़े–बड़े युद्ध किए? किसके लिए लाखों का बलिदान हुआ? उत्तर हो सकता है भारत की भूमि के लिए। किंतु भारत से तात्पर्य क्या जड़ भूमि से है? क्या हमने हिमालय के पत्थर और गंगा के जल की रक्षा की है? हमारे अवतारों ने किस हेतु जन्म लिया था? उनको हम भगवान् का अवतार क्यों कहते हैं? इस लेख में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए वे अनेक वैचारिक प्रश्नों का साक्षात्कार पाठकों को कराते हैं।

हमारा धर्म हमारे राष्ट्र की आत्मा है। बिना धर्म के राष्ट्र जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। भारतीय राष्ट्र न तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए भू–खंड से बन सकता है और न तीस करोड़ मनुष्यों के झुंड से। एक ऐसा सूत्र चाहिए, जो तीस करोड़ को एक–दूसरे से बांध सके, जो तीस कोटि को इस भूमि में बांध सके। वह सूत्र हमारा धर्म ही है। बिना धर्म के भारतीय जीवन का चैतन्य ही नष्ट हो जाएगा, उसकी प्रेरक शक्ति ही जाती रहेगी। अपनी धार्मिक विशेषता के कारण ही संसार के भिन्न–भिन्न जन समूहों में हम भी राष्ट्र के नाते खड़े हो सकते हैं। धर्म के पैमाने से ही हमने सबको नापा है। धर्म की कसौटी पर ही कसकर हमने खरे–खोटे की जांच की है। हमने किसी को महापुरुष मानकर पूजा है तो इसलिए कि उनके जीवन में पग–पग हमको धार्मिकता दृष्टिगोचर होती है। राम हमारे आराध्य देव बनकर रहे हैं और रावण सदा से घृणा का पात्र बना है। क्यों? राम धर्म के रक्षक थे और रावण धर्म का विनाश करना चाहता था। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों भाई–भाई थे, दोनों राज्य चाहते थे, एक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, तो दूसरे के प्रति घृणा।

दीनदयाल जी राष्ट्र के समक्ष उपस्थित विभिन्न वैचारिक चुनौतियों के अंतर्गत द्विसंस्कृतिवाद तथा बहुसंस्कृतिवाद भी मानते हैं। अपने लेख में वे भारत को संस्कृति वाला राष्ट्र मानते हैं। अपने लेख 'राष्ट्रजीवन की समस्याएं' राष्ट्रधर्म में लिखते हैं–

भारत में एक ही संस्कृति रह सकती है। एक से अधिक संस्कृतियों का नारा देश के टुकड़े–टुकड़े करके हमारे जीवन का विनाश कर देगा। अतः आज लीग का द्विसंस्कृतिवाद, कांग्रेस का प्रच्छन्न द्विसंस्कृतिवाद तथा साम्यवादियों का बहुसंस्कृतिवाद नहीं चल सकता। आज तक एक–संस्कृतिवाद को संप्रदायवाद कहकर ठुकराया गया, किंतु अब कांग्रेस के विद्वान भी अपनी गलती समझकर इस एक–संस्कृतिवाद को अपना रहे हैं। इसी भावना और विचार से भारत की एकता तथा अखंडता बनी रह सकती है तथा तभी हम अपनी संपूर्ण समस्याओं को सुलझा सकते हैं।

उनके अनुसार भारत में चार प्रधान वर्ग दिखाई पड़ते हैं, जिसकी व्याख्या उन्होंने निम्नवत् की है–

अर्थवादी पहला वर्ग, अर्थवादी संपत्ति को ही सर्वस्व समझता है तथा उसके स्वामित्व एवं वितरण में ही सब प्रकार की दुरवस्था की जड़ मानकर उसमें सुधार करना ही अपना एकमेव कर्तव्य समझता है। उसका एकमेव लक्ष्य 'अर्थ' है। साम्यवादी एवं समाजवादी इस वर्ग के लोग हैं। इनके

अनुसार भारत की राजनीति का निर्धारण अर्थनीति के आधार पर होना चाहिए। संस्कृति एवं मत को वे गौण समझकर अधिक महत्व देने को तैयार नहीं हैं।

राजनीतिवादी दूसरा वर्ग है। यह जीवन का संपूर्ण महत्व राजनीतिक प्रमुख प्राप्त करने में ही समझता है तथा राजनीतिक दृष्टि से ही संस्कृति, मजहब तथा अर्थनीति की व्याख्या करता है। अर्थवादी यदि एकदम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अथवा बिना मुआवजा दिए जमींदारी उन्मूलन चाहता है, तो राजनीतिवादी अपने राजनीतिक कारणों से ऐसा करने में असमर्थ है। उसके लिए इस प्रकार संस्कृति एवं मजहब का भी मूल्य अपनी राजनीति के लिए ही है, अन्यथा नहीं। इस वर्ग के अधिकांश लोग कांग्रेस में हैं, जो आज भारत की राजनीतिक बागडोर संभाले हुए हैं।

मतवादी तीसरा वर्ग, मजहब परस्त या मतवादी है। इसे धर्मनिष्ठ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि धर्म मजहब या मत से बड़ा तथा विशाल है। यह वर्ग अपने–अपने मजहब के सिद्धांतों के अनुसार ही देश की राजनीति अथवा अर्थनीति को चलाना चाहता है। इस प्रकार का वर्ग मुल्ला–मौलवियों अथवा रूढ़िवादी कट्टरपंथियों के रूप में अब भी थोड़ा बहुत विद्यमान है, यद्यपि आजकल उसका बहुत प्रभाव नहीं रह गया है।

संस्कृतिवादी चौथा वर्ग है। इसका विश्वास है कि भारत की आत्मा का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृति ही है। अतः अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यदि हमारा सांस्कृतिक ह्रास हो गया तथा हमने पश्चिम के अर्थ प्रधान अथवा भोग प्रधान जीवन को अपना लिया, तो हम निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। यह वर्ग भारत में बहुत बड़ा है। इसके लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा कुछ अंशों में कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस के ऐसे लोग राजनीति को केवल संस्कृति का पोषकमात्र ही मानते हैं, संस्कृति का निर्णायक नहीं। हिंदीवादी सब लोग इसी वर्ग के हैं।

जहां संस्कृतिवाद के दृष्टिकोण को सार्थक मानते हैं, वहीं इसके विभिन्न स्वरूपों एवं समस्याओं के

प्रति सचेत भी हैं। संस्कृति का स्वरूप कैसा हो इसमें कौन सा तत्व हो आदि विषयों पर हो रहे विवाद को भी वे एक समस्या ही मानते हैं, वे कहते हैं–

आज भी भारत में प्रमुख समस्या सांस्कृतिक ही है। वह भी आज दो प्रकार से उपस्थित है, प्रथम संस्कृति को ही भारतीय जीवन का प्रथम तत्व मानना तथा दूसरे यदि इसे मान लें, तो उस संस्कृति का रूप कौन सा हो? विचार के लिए यद्यपि यह समस्या दो प्रकार की मालूम होती है, किंतु वास्तव में है एक ही। क्योंकि एक बार संस्कृति का जीवन को प्रमुख एवं आवश्यक तत्व मान लेने पर उसके स्वरूप के संबंध में झगड़ा नहीं रहता, न उसके संबंध में किसी प्रकार का मतभेद ही उत्पन्न होता है। यह मतभेद तो तब उत्पन्न होता है, जब अन्य तत्वों को प्रधानता देकर संस्कृति को उसके अनुरूप उन ढांचों में ढकने का प्रयत्न किया जाता है।

अंततः वे एक संस्कृतिवाद को ही उत्तम मार्ग मानते हैं तथा राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व बताते हैं। वे लिखते हैं–

केवल एक–संस्कृतिवादी लोग ही ऐसे हैं, जिनके समक्ष और कोई ध्येय नहीं है तथा जैसा कि हमने देखा, संस्कृति ही भारत की आत्मा होने के कारण वे भारतीयता की रक्षा एवं विकास कर सकते हैं। शेष सब तो पश्चिम का अनुकरण करके या तो पूंजीवाद अथवा रूस की तरह आर्थिक प्रजातंत्र तथा राजनीतिक पूंजीवादी का निर्माण करना चाहते हैं। अतः उनमें सब प्रकार की संभावना होते हुए भी इस बात की संभावना कम नहीं है कि उनके द्वारा भी भारतीय आत्मा तथा भारतीयत्व का विनाश हो जाए। अतः आज की प्रमुख आवश्यकता तो यह है कि एक–संस्कृतिवादियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाए। तभी हम गौरव और वैभव से खड़े हो सकेंगे तथा भारत–विभाजन जैसी भावी दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे।

15 अगस्त, 1947 को हमने एक मोर्चा जीत लिया। हमारे देश से अंग्रेजी राज्य विदा हो गया। उस

राज्य के कारण हमारी प्रतिभा के विकास में जो बाधाएं उपस्थित की जा रही थीं, उनका कारण हट गया, हम अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हो गए। अपनी आत्मानुभूति का मार्ग खुल गया। किंतु अभी भी मानव की प्रगति में हमको सहायता करनी है। मानव द्वारा छेड़े गए युद्ध में जिन–जिन शस्त्रों का प्रयोग हमने अब तक किया है, जिनके चलाने में हम निपुण हैं तथा जिन पर पिछली सहस्राब्दियों में जंग लग गई थी, उन्हें पुनः तीक्ष्ण करना है तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देकर मानव को विजय बनाना है। आज यदि हमारे मन में उन पद्धतियों के विषय में ही मोह पैदा हो जाए, जिनके पुरस्कर्ताओं से हम अब तक लड़ते रहे हैं, तो यही कहना होगा कि हम न तो स्वतंत्रता का सच्चा स्वरूप समझ पाए हैं और न अपने जीवन के ध्येय को ही पहचान पाए हैं। हमारी आत्मा ने अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह केवल इसलिए नहीं किया कि दिल्ली में बैठकर राज्य करने वाला एक अंग्रेज था, अपितु इसलिए भी कि हमारे दिन–प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन की गति में विदेशी पद्धतियां, रीति–रिवाज, विदेशी दृष्टिकोण और आदर्श अड़ंगा लगा रहे थे, हमारे संपूर्ण वातावरण को दूषित कर रहे थे, हमारे लिए सांस लेना भी दूभर हो गया था। आज यदि दिल्ली का शासनकर्ता अंग्रेज के स्थान पर हममें से ही एक, हमारे ही रक्त और मांस का एक अंश हो गया है, तो हमें इसका हर्ष है, संतोष है किंतु हम चाहते हैं कि उनकी भावनाएं और कामनाएं भी हमारी भावनाएं और कामनाएं हों। जिस देश की मिट्टी से उसका शरीर बना है, उसके प्रत्येक रंजकण का इतिहास उसके शरीर के कण–कण से प्रति ध्वनित होना चाहिए। तीस कोटि के हृदयों को समष्टिगत भावनाओं से उसका हृदय उद्वेलित होना चाहिए तथा उनके जीवन के विकास के अनुकूल, उनकी प्रकृति और स्वभाव अनुसार तथा उनकी भावनाओं और कामनाओं के अनुरूप पद्धतियों की सृष्टि उसके द्वारा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमको कहना होगा कि अभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई बाकी है। अभी हम अपनी आत्मानुभूति में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं कर पाए हैं।

आर्थिक स्वाधीनता के साथ–साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। आत्मानुभूति के प्रयत्नों में जिन सामाजिक व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों की राष्ट्र अपनी सहायता के लिए सृष्टि करता है अथवा जिन रीति–रिवाजों में उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वे ही यदि कालावपात से उसके मार्ग में बाधक होकर उसके ऊपर भार रूप हो जाएं तो उनसे मुक्ति पाना भी प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। यात्रा की एक मंजिल में जो साधन उपयोगी सिद्ध हुए हैं वे दूसरी मंजिल में भी उपयोगी सिद्ध होंगे यह आवश्यक नहीं। साधन तो प्रत्येक मंजिल के अनुरूप ही चाहिए तथा इस प्रकार प्रयाण करते हुए प्राचीन साधनों का मोह परतंत्रता का ही कारण हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल उन तंत्रों का समष्टिगत नाम है जो स्वानुभूति में सहायक होते हैं। राष्ट्र की सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो अत्यंत महत्व की है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र के संपूर्ण शरीर में प्राणों के समान संचार करती है। प्रकृति के तत्वों पर विलय पाने के प्रयत्न में तथा मानवानुभूति की कल्पना में मानव जिस जीवन दृष्टि की रचना करता है, वह उसकी संस्कृति है। संस्कृति कभी गतिहीन नहीं होती अपितु वह निरंतर गतिशील हो फिर भी उसका अपना एक अस्तित्व है। नदी के प्रवाह की भांति निरंतर गतिशील होते हुए भी वह अपनी निजी विशेषताएं रखती हैं, जो उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले समाज के संस्कारों तथा उस सांस्कृतिक भावना से जन्य राष्ट्र के साहित्य, कला, दर्शन, स्मृति शास्त्र, समाज रचना इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न अंग अंगों में व्यक्त होती हैं। परतंत्रता के काल में इन सब पर प्रभाव पड़ जाता है तथा स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। आज स्वतंत्र होने पर आवश्यक है कि हमारे प्रवाह की संपूर्ण बाधाएं दूर हों तथा हम अपनी प्रतिभा अनुरूप राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्रों में विकास कर सकें। राष्ट्र भक्ति की भावना को निर्माण करने और उसको साकार स्वरूप देने का श्रेय भी राष्ट्र की संस्कृति को ही है तथा वही राष्ट्र की संकुचित सीमाओं को तोड़कर मानव की एकात्मता का अनुभव कराती है। अतः संस्कृति की स्वतंत्रता परमावश्यक है। बिना उसके राष्ट्र की स्वतंत्रता निरर्थक ही नहीं, टिकाऊ भी नहीं रह सकेगी। ◆

(लेखक–लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष है)

मो. : 8750820740

पुण्यतिथि

प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे कल्याण सिंह

–वीरेन्द्र सिंह लोधी

भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह को विवादित बाबरी ढाँचा के विध्वंस के पश्चात नवीन पहचान मिली थी। इस घटना के पश्चात उन्हें हिंदुत्व के सम्राट के रूप में देखा जाने लगा था। इस घटना ने उन्हें हिंदुत्ववादी राजनीति में नायक बना दिया। यह घटना उनके जीवन की उपलब्धि के रूप में देखी जाती है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी, 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के मढ़ौली ग्राम के लोधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री तेजपाल लोधी और माता का नाम श्रीमती सीता देवी था। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। अपने पिता के कारण उनका झुकाव भी संघ की ओर हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया।

कल्याण सिंह ने प्रथम बार वर्ष 1962 में अतरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी पराजय हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने 1967, 1969 और 1974 में निरंतर अतरौली से विधानसभा क्षेत्र से विजय प्राप्त की। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था। उन्होंने वर्ष 1977 में अतरौली विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार भी विजय प्राप्त की। वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। आपातकाल की समयावधि में कल्याण सिंह को कारावास भेज दिया गया। वह लगभग 21 महीने कारावास में रहे किन्तु इंदिरा लहर के कारण 1980 के चुनाव में उन्हें

पराजय का मुंह देखना पड़ा। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। वर्ष 1985 में पुनः उन्हें विजय प्राप्त हुई। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वह 1989 में पुनः विजय प्राप्त करके विधायक दल के नेता बने।

वर्ष 1991 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 425 में से 221 सीटें प्राप्त हुई थीं। वह प्रथम बार 24 जून 1991 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, परन्तु अगले वर्ष 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के पश्चात उन्होंने अपने पद से त्याग–पत्र दे दिया। इसके पश्चात नवम्बर 1993 में उन्होंने अतरौली व कासगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों ही क्षेत्रों से विजय प्राप्त की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, परन्तु मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन की सरकार बना ली। कल्याण सिंह विधान सभा में विपक्ष के नेता बने।

कल्याण सिंह ने प्रथम बार वर्ष 1962 में अतरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी पराजय हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने 1967, 1969 और 1974 में निरंतर अतरौली से विधानसभा क्षेत्र से विजय प्राप्त की। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था। उन्होंने वर्ष 1977 में अतरौली विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार भी विजय प्राप्त की। वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया।

इसके पश्चात उन्होंने 21 सितम्बर 1997 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनवाई, किन्तु यह सरकार अधिक समय तक नहीं चली। बहुजन समाज पार्टी ने 21 अक्टूबर 1997 को कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। चूंकि कल्याण सिंह को पहले से ही इसका आभास था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस विधायक नरेश अग्रवाल के सम्पर्क बना लिया था। नरेश अग्रवाल ने शीघ्रता से नई पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन कर किया और कल्याण सिंह को 21 विधायकों का समर्थन दिलवा दिया। परिणाम स्वरूप कल्याण सिंह की सरकार बच गई। उन्होंने नई सरकार में नरेश अग्रवाल को ऊर्जा विभाग का कार्यभार सौंप दिया। उनका यह कार्यकाल 12 नवम्बर 1999 तक रहा। इसके पश्चात दिसम्बर 1999 में कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ दी। वह जनवरी 2004 में पुनः पार्टी में सम्मिलित हो गए। वर्ष 2004 लोकसभा चुनाव में वह लोकसभा क्षेत्र बुलन्दशहर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और विजय प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 2009 में पुनः पार्टी छोड़ दी और एटा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की।

कल्याण सिंह 4 सितम्बर, 2014 को राजस्थान के राज्यपाल बने। उनका यह कार्यकाल 8 सितम्बर, 2019 तक रहा। उन्हें जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। उनका यह कार्यकाल 12 अगस्त 2015 तक रहा।

कल्याण सिंह लम्बे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। राम मनोहर लोहिया ऑफ मेडिकल साइंस में उनका उपचार चल रहा था, परन्तु स्थिति गंभीर होने पर 4 जुलाई, 2021 को उन्हें लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया, जहां 21 अगस्त को उनका देहांत हो गया। गंगा के तट नरोरा में 23 अगस्त को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि कल्याण सिंह ने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जन संघ और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। कल्याण सिंह भारत के कोने–कोने में विश्वास का नाम बन गए थे। प्रतिबद्ध

निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय जनकल्याण में सदैव (चाहे वह विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे राज्यपाल की जिम्मेदारी हो) हर एक के लिए प्रेरणा का केंद्र बने। जनसामान्य के विश्वास का प्रतीक बने। देश ने मूल्यवान व्यक्तित्व वाला नेता खोया है। हम उनके आदर्शों, उनके संकल्पों को लेकर अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।"

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सर्वमान्य नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार्य हो चुके थे। किन्तु इससे पूर्व वाराणसी में दिसम्बर 2013 में कल्याण सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम की नई परिभाषा बताई थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को 'नर और इंद्र' का स्वरूप बताया था। इसी प्रकार उन्होंने अंग्रेजी में 'MODI' का फुलफॉर्म Man of Determination and inspiration अर्थात 'दृढ़ संकल्प और प्रेरणा का व्यक्ति' उन्होंने कहा था कि इस प्रकार मोदी के साथ देश के निर्धन, आदिवासी, वंचित, किसान, युवा और व्यापारी सहित सभी वर्गों का कल्याण जुड़ा हुआ है। मोदी राष्ट्रीयता, भारतीयता एवं हिंदुत्व के सशक्त प्रतीक हैं। नरेंद्र मोदी की देशप्रेम से ओतप्रोत भावना और उनके विचारों की विशालता के आगे धर्म, जाति और क्षेत्र के बंधन अब टूट रहे हैं। मोदी निश्चित रूप पर इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मोदी वह सब कार्य करेंगे, जो भारत को वैश्विक पटल पर नई ख्याति, सम्मान और पहचान दिलाएंगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सम्पूर्ण विश्व में भारत एक नये सिरे से प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित करेगा।

बाबू जी (कल्याण सिंह) को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से अत्यधिक लगाव था। एक बार उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था– "संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद–बूंद में समाए हुए हैं। मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटकर जाए।" ईश्वर ने उनकी यह इच्छा पूर्ण कर दी। 21 अगस्त, 2025 में बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई, जिसे 'हिन्दू गौरव दिवस' के रूप में भी मनाया गया, ◆

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं)

मो. : 9627965555

देश सेवा के लिए रहें तैयार
पुलिस भर्ती का बम्पर उपहार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा

वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित भर्ती परीक्षा कैलेंडर

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) कुल पद : 921 (लिखित परीक्षा : अक्टूबर/नवंबर, 2025)	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए कुल पद : 1,129 (लिखित परीक्षा : अक्टूबर/नवंबर, 2025)

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल	कुल पद : 4,543 विज्ञप्ति अवधि : अगस्त, 2025
सहायक रेडियो परिचालक	कुल पद : 44 विज्ञप्ति अवधि : अक्टूबर/नवंबर, 2025
कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	कुल पद : 1,153 विज्ञप्ति अवधि : अक्टूबर/नवंबर, 2025
आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी (महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस, जेल वॉर्डर एवं घुड़सवार पुलिस	कुल पद : 22,605 विज्ञप्ति अवधि : नवंबर, 2025
पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)	कुल पद : 345 विज्ञप्ति अवधि : दिसंबर, 2025

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

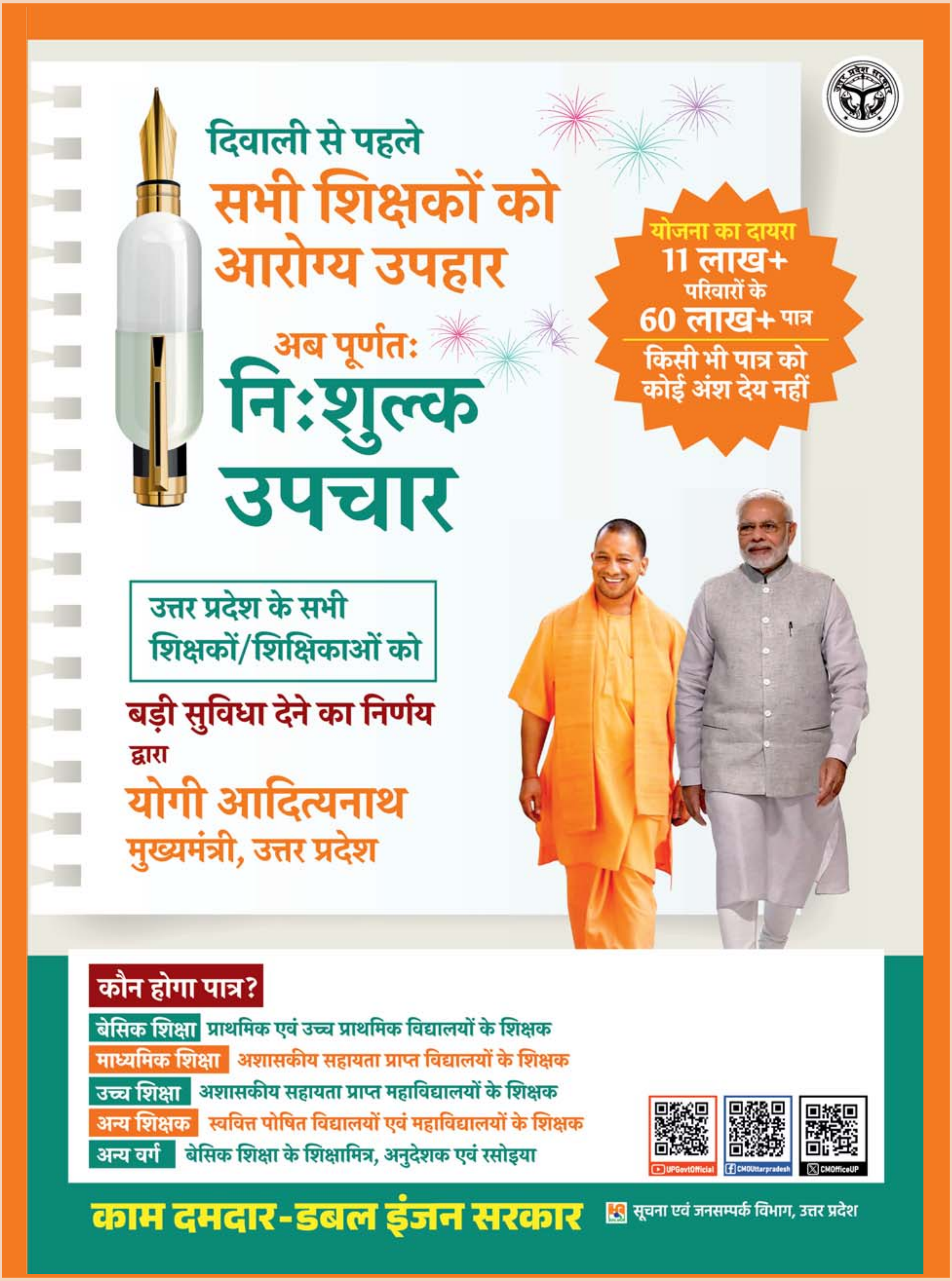

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए विशाल सिंह, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित, सम्पादक—चन्द्र विजय वर्मा।